



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

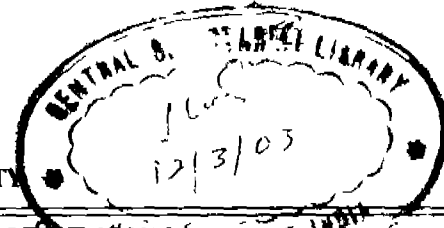
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 261]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 7, 2002/आश्विन 15, 1924

No. 261]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 7, 2002/ASVINA 15, 1924

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटन रोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

(अधिसूचना)

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर, 2002

अंतिम जांच परिणाम

विषय : कतर से कास्टिक सोडा के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच।

संख्या 55/1/2001-डी जी ए डी.—वर्ष 1995 में यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 तथा उसकी सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 को ध्यान में रखते हुए;

क. प्रक्रिया

1. जाच के सबध में अधोलिखित प्रक्रिया का पालन किया गया है :-

- (1) निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके पश्चात् प्राधिकारी भी कहा गया है) को उपरोक्त नियमों के अंतर्गत में ग्रासिम इंडस्ट्रीज, में गुजरात अल्कलीज एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड में सर्व कैम इंडस्ट्रीज लि एन, में डी सी डब्ल्यू और में इंडियन रेयन एण्ड इंडस्ट्रीज लि जिन्होंने घरेलू उद्योग का प्रतिविधित्व किया में अल्कली मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एएमएआई) जिसे इसके पश्चात् याचिकाकर्ता कहा गया है । से लिखित आवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें कतर (जिसे इसके बाद बाद सबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के या वहा से निर्यात किए गए सोडियम हाइड्रोक्साइड जो सामान्य तथा कास्टिक सोडा (जिसे इसके बाद सबद्ध वस्तु भी कहा गया है)के नाम से जाना जाता है के पाटन का आरोप लगाया गया था । जाच शुरुआत के बाद इस याचिका को में सील कैमिकल्स कम्पलेक्स, पटियाला, पंजाब, में बिहार कास्टिक एण्ड कैमिकल्स लि बिहार, में जयश्री कैमिकल्स लि, उड़ीसा तथा में आग्र शुगर्स लि, सगोण्डा एकक द्वारा समर्थन दिया गया था ।

- (ii) याचिकाकर्ता द्वारा तैयार किए गए आवेदन की प्रारंभिक जांच से कतिपय त्रुटियों का पता चला जिसे बाद में याचिकाकर्ता द्वारा इन्हें दूर कर दिया गया । इसलिए इस याचिका का उचित रूप से दस्तावेज युक्त माना गया ।
- (iii) प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर कतर से संबद्ध वस्तु के आयातों के खिलाफ जांच शुरू करने का निर्णय लिया । प्राधिकारी ने उक्त नियमों के उप-नियम 5 (5) के अनुसार जांच की कार्रवाई शुरू करने से पहले पाटन के आरोप की प्राप्ति के विषय में नई दिल्ली स्थित कतर के दूतावास को सूचित किया ।
- (iv) प्राधिकारी ने कतर के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु जो, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की अनुसूची 1 के सीमाशुल्क कोड 281511 तथा 281512 के अंतर्गत वर्गीकृत है, के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करते हुए, दिनांक 8 10 2001 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया ।
- (v) प्राधिकारी ने दिनांक 18 1 2002 में प्रारंभिक जांच परिणामों को अधिसूचित किया तथा प्रारंभिक जांच परिणामों की एक प्रति निम्नलिखित हितबद्ध पार्टियों को भेजी जिनसे पत्र की तारीख के घालीस दिनों के भीतर प्रारंभिक जांच परिणामों पर अपने विचार यदि कोई हो तो प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था ।

आयातक/उपयोक्ता

1. मै अमय कैमिकल्स लि बड़ौदा
2. मै अलब्राइट विल्सन कैमिकल्स लि मुम्बई
3. मै अरविन्द मिल्स लि., अहमदाबाद
4. मै बिडला सेल्यूलोज लि., भरुच
5. मै सेंद्रल पल्प मिल्स लि., दिल्ली
6. मै दीपक नाईट्राईट लि., नन्देसरी
7. मै गोदरेज सोप्स लि., मुम्बई
8. मै गुजरात इलैक्ट्रीसीटि बोर्ड, बड़ोदरा
9. मै गुजरा नर्मदा फर्टिलाइजर्स क लि भरुच
10. मै गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लि., बड़ोदरा
11. मै हिन्दुस्तान लीवर लि., मुम्बई
12. मै आईसीआई इंडिया लि., वलसाड

13. मै इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर्स कोप. लि, गांधीनगर
14. मै इंडियन आयल कारपोरेशन लि बड़ोदरा
15. मै इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लि, बड़ोदरा
16. मै जयसिंघ डाईकेम लि. मुम्बई
17. मै लिफ फार्मा लि, बड़ौदा
18. मै मेघमानी आरगेनिक्स लि., अहमदाबाद
19. मै नर्मदा चेमातुर पेट्रोकेमिकल्स लि., भरुच
20. मै. निरमा लि., अहमदाबाद
21. मै पीएबी केमिकल्स (प्रा) लि, बड़ौदा
22. मै रामा न्यूजप्रिन्ट्स एण्ड पेपर्स लि, सूरत
23. मै. रुबामिन लि., बड़ौदा
24. मै टार्रन्ट गुजरात बायो-टेक लि, बड़ौदा
25. मै ट्रासपेक इंडस्ट्रीज लि, बड़ोदरा
26. मै नेशनल एल्यूमीनियम लि., भुवनेश्वर उड़ीसा
27. मै सी जे शाह एण्ड कम्पनी, मुम्बई

निर्यातक

मै कतर विनाईल कंपनी कतर

घरेलू उद्योग

मै अल्कली मनुफक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया

- (vi) प्राधिकारी ने नई दिल्ली स्थित संबद्ध देश के दूतावास को भी प्रारंभिक जाच परिणामों की एक प्रति भेजी तथा उससे आग्रह किया कि वे संबद्ध वस्तुओं के निर्यातकों एवं अन्य हितबद्ध पार्टियों का प्रारंभिक जाच परिणामों पर अपने विचार पत्र की तारीख के चालीस दिनों के अन्दर देने की सलाह दे ।
- (vii) प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पार्टियों को दिनांक 29.4.2002 को मौखिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने का एक अवसर दिया सभी पार्टियों से आग्रह किया गया कि वे व्यक्त किए गए अपने विचार लिखित रूप में भी प्रस्तुत करें । पार्टियों का विरोधी पार्टियों द्वारा व्यक्त विचारों की प्रतिया प्राप्त करने और खंडन, यदि कोई हो, देने की सलाह दी गई थी ।

- (viii) प्रारंभिक जांच परिणामों/सार्वजनिक सुनवाई में निम्नलिखित हितबद्ध पार्टियों द्वारा अनुरोध किये गये थे -
- (i) मै अल्कली मनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया
 - (ii) मे नालको
 - (iii) मे कतर विनाईल कंपनी लि. की ओर से मे. इकानोमिक लाज प्रेक्टिस मुम्बई
- (ix) प्राधिकारी ने उसके द्वारा रखी गई सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपीनय अंश को उपलब्ध कराया और उसे नियम 6(7) के अनुसार हितबद्ध पार्टियों के निरीक्षण के लिए खुला रखा ।
- (x) केन्द्रीय उ.शु.एवं सी.शु. बोर्ड (सी बी ई सी) से जांच की अवधि सहित पिछले तीन वर्षों में भारत में निर्मित संबद्ध वस्तुओं के आयातों का ब्यौरा देने का आग्रह किया गया । कांडला पोर्ट ट्रस्ट से भी पोतलदान ब्यौरों के लिए अनुरोध किया गया । कांडला सीमा शुल्क तथा कांडला पत्तन के प्राधिकारियों से आयातों के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी ।
- (xi) प्रारंभिक जांच परिणामों की घोषणा से पहले हितबद्ध पार्टियों द्वारा दिए गये तर्कों जिन्हें अधिसूचित प्रारंभिक जांच परिणामों में प्रकाशित किया जा चुका है को संक्षिप्तता की वजह से यहां दोहराया नहीं गया है । तथापि हितबद्ध पार्टियों द्वारा बाद में दिए गए तर्कों पर प्रारंभिक जांच परिणामों तथा/अथवा इन परिणामों में समुचित कार्रवाई की गई है ।
- (xii) पूर्वोक्त नियमों के नियम 16 के अनुसार इन जांच, परिणामों के लिए विचार किए गए आवश्यक तथ्य/आधार का दिनांक 20.9.2002 को ज्ञात हितबद्ध पार्टियों को खुलासा किया गया । और इस पर प्राप्त टिप्पणियों पर भी इन जांच परिणामों में विधिवत विचार किया गया है ।
- (xiii) सामान्य स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएपीपी) तथा याचिकाकर्ता द्वारा दी गई सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तु तथा उसे बनाने और बेचने की लागत की इष्टतम उत्पादन लागत को निकालने के लिए लागत संबंधी जांच भी की गई थी । निम्नलिखित घरेलू उत्पादकों के लागत संबंधी आंकड़े उपलब्ध किए गए थे तथा उनका विश्लेषण किया गया था -
- 1 मै डीसीडब्ल्यू
 - 2 गुजरात अल्कलीज एण्ड कैमिकल्स लि , बडोदरा

- 3 सर्व केम इंडस्ट्रीज लि जगाधिया
- 4 इंडियन रेयन एण्ड इंडस्ट्रीज लि, वेरावल, गुजरात
- 5 मै ग्रासिम इंडस्ट्रीज
- 6 सील कमिकल्स कम्पलेक्स, पटियाला पंजाब
- 7 मै बिहार कास्टिक एण्ड कैमिकल्स लि बिहार
- 8 मै जयश्री कैमिकल्स लि, उड़ीसा
- 9 मै आध्र सुगर्स लि, सम्माण्डा

(xiv) प्राधिकारी ने याचिकाकर्ताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का आवश्यक सीमा तक सत्यापन किया तथा मैसर्स कतर दिनाईल कम्पनी कतर द्वारा उपलब्ध कराए गए आकड़ों का 10 तथा 11 सितम्बर 2002 को मौके पर सत्यापन भी किया।

(xv) XXX यह चिन्ह इस अधिसूचना में किसी हितबद्ध पार्टियों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का द्योतक है और प्राधिकारी द्वारा नियमों के अन्तर्गत इसे गोपनीय ही माना गया है।

(xvi) यह जाच 1 जनवरी, 2001 से 30 सितम्बर, 2001 अर्थात् जाच अवधि के लिए की गयी थी।

(ख) निर्यातकों, आयातकों एवं अन्य हितबद्ध पार्टियों के विचार

1. मैसर्स अलकली मनुफैक्चर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ए.एम.ए.आई.) के विचार

(क) याचिकाकर्ता के विचार, जांचाधीन उत्पाद एवं समान वस्तु

(अ) याचिकाकर्ता ने प्रारम्भिक जाच परिणामों में यथा उल्लिखित जांचाधीन उत्पाद तथा समान वस्तु पर दिए गए अपने अनुरोधों को दोहराया है।

प्रकटन विवरण के उत्तर में निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं :-

घरलू उद्योग ने अपने पूर्ववर्ती अनुगन्धा का दाहराया है और उल्लेख किया है कि चूंकि विचारधीन उत्पाद समान वस्तु और घरलू उद्योग के आधार के मुद्दे के विरोध में कोई अनुरोध नहीं किया गया है और न ही इस मुद्दे पर कोई आपत्ति उठाई गई है, इसलिए उन्होंने प्रारम्भिक जाच परिणामों की पुष्टि करने का अनुरोध किया है।

(ख) सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत तथा पाटन

पाटन

(1) क्योंकि कतर के निर्यातक ने जबाब दिया है, तथापि आयातों ने जबाब नहीं दिया है निम्न हमारे इस दावे की पुष्टि होती है कि आयातकों/व्यापारियों को इस बात की

भलीभाँति जानकारी थी कि जिस कीमत पर सामग्री का आयात किया गया है, यह पाटित कीमत है। यह पूर्ण व्यापक आधार पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का उपर्युक्त मामला बनता है।

- (ii) निर्यातक न प्रश्नावली के उत्तर का अगापनीय सारांश दायर नहीं किया है।
- (iii) जाच अवधि के दौरान भारत में कास्टिक सोडा का आयात न होने के संबंध में निर्यातक का तर्क उचित नहीं है क्योंकि संबंधित तथ्य निर्यातों का है न कि आयातों का।
- (iv) उत्पाद को निर्यात विभिन्न शर्तों जैसे खरीद का पुष्टिकृत प्रस्ताव/आर्डर, बीजक तथा पुन बिक्री का प्रस्ताव आदि के तहत किया गया माना जा सकता है।
- (v) वर्तमान मामले में, जाच अवधि के दौरान निर्यातक द्वारा भारतीय व्यापारी को आपूर्ति का प्रस्ताव किया गया था।
- (vi) जहां तक निर्यातक के सामान्य मूल्य का संबंध है, निर्यातक की उत्पादन लागत की विस्तार से जाच करने की आवश्यकता है।
- (vii) याचिकाकर्ता पुरजोर अनुरोध करते हैं कि किसी भी परिस्थिति में निर्यातक के लिए उत्पादन लागत कम नहीं हो सकती है क्योंकि उन्होंने 678 मिलियन अमरीकी डालर का भारी निवेश किया है। कंपनी ने उत्पादन की वास्तविक लागत प्रस्तुत नहीं की है। कंपनी ने तुलन पत्र, लाभ तथा हानि खाता एवं प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी प्रस्तुत नहीं की है।
- (viii) याचिकाकर्ता ने क्रेडलिस्ट मामले में माननीय उच्चतम न्यायलय के निर्णय को उद्धृत किया है तथा यह इंगित किया है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट का नहीं उपलब्ध कराये जाने को ध्यान में रखते हुए नियम 6(8) लागू होता है।
- (ix) याचिकाकर्ता ने यह भी अनुरोध किया है कि सामान्य खर्चों के आवंटन तथा सविमान, सेवाओं की उपर्युक्त लागत तथा व्याज लागत इत्यादि से संबंधित उपर्युक्त जाच का आकलन सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए।
- (x) ई यू दिशानिर्देशों के अनुसार निर्यात कीमत के साक्ष्य का अलग-अलग बीजक वार सौदा या प्रस्तावों से प्राप्त किया जाए। पाटन के संबंध में अमरीकी प्रश्नावली में भी उन सभी बिक्रियों का जिनकी आपूर्ति जबाब देने की तारीख तक पूरी नहीं की गयी है का कीमत निर्धारित के प्रयाजनाथ शामिल करना होता है।
- (xi) हितबद्ध पार्टियाँ पाटन मार्जिन निर्धारित करने के अधिकार क्षेत्र तथा पाटनरोधी शुल्क वसूल करने के अधिकार क्षेत्र के संबंध में भ्रमित हैं। ये दोनों मुद्दे पूर्णतः अलग-अलग मुद्दे हैं।

- (xii) आयातों के सबध में तर्क अनुचित है क्योंकि पाटन का तथ्य निर्यातों से उत्पन्न होता है तथा भविष्य में आयातों पर ऐसा शुल्क लगाये जाने योग्य होता है ।
- (xiii) निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पूर्व में किये गये प्रस्ताव दिए आर्डर को पी आई बी तथा सीमलैस ट्यूब के मामले में पाटनराधी कार्रवाई करने के लिए उपयुक्त माना है ।
- (xiv) प्रारम्भिक जाच परिणामों से पहले सुनवाई के सबध में नालकों के तर्क को न्यूजप्रिंट के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आलोक में नजरअदाज किया जा सकता है ।
- (xv) विभिन्न नियमों में प्रारम्भिक जाच परिणामों से पहले सुनवाई का प्रावधान नहीं है ।
- (xvi) हाल ही में पूरे हुए विट्रीफाईड टाईल्स मामले में भी वित्त मंत्रालय, संबंधित पार्टियों की किसी सुनवाई पर सहमत नहीं हुआ था ।
- (xvii) एक आयातक होने के नाते, नालका पाटन तथा पाटनमार्जिन का मुद्दा नहीं उठा सकता है और नालकों न तो तथ्यात्मक सूचना का प्रतिनिधि है और न ही नालकों को कास्टिक सोडा के उत्पादन तथा बिक्री के बारे में कोई वास्तविक अनुभव तथा ज्ञान है ।

प्रकटन विवरण के जबाब में निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं:-

- (i) जहां तक पाटन का सबध है, घरेलू उद्योग न ऐसे निर्यात के सबध में विभिन्न प्रकार के प्रस्तावों/दस्तावेजों के सबध में अपने अनुरोधों को दोहराया है जिन्हें देश में किया जा सकता है तथा ये आगे इस तथ्य को दोहराते हैं कि जाच अवधि के दौरान किये गये पोतलदान की कम प्रासंगिक है ।
- (ii) याचिकाकर्ता ने यह भी उल्लेख किया है कि चूंकि सामान्य मूल्य का निर्धारण अब निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा याचिकाकर्ताओं द्वारा किये गये विभिन्न अनुरोधों तथा उत्पादन लागत के पुन आकलन को ध्यान में रखने के बाद किया गया है, इसलिए प्रस्तावित निर्धारण की पुष्टि की जानी चाहिए ।

(ग) क्षति, कारणात्मक संबंध तथा अन्य मुद्दे

- (i) निर्यातक की क्षमता का सृजन विभिन्न बाजारों को संभावित बाजारों जिनमें भारत भी शामिल है, के रूप में मानकर किया गया है ।
- (ii) कतर से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति के खतरे को दूसरे देशों में पहले से ही लागू पाटनराधी शुल्क के परिप्रेक्ष्य में देखे जाने की आवश्यकता है ।

- iii. निर्यातक द्वारा अधिष्ठापित क्षमता 290000 मी०टन उनकी घरेलू मांग की तुलना में बहुत अधिक है ।
- iv. कंपनी ने यह भी माना कि वह अपना ध्यान जीसीसी देशों,, आस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीकी बाजारों पर केन्द्रित करना चाहती हैं । निर्यातक के लिए भारतीय बाजार लाभकारी है ।
- v. भारतीय उत्पादक समझते हैं कि निर्यातक ने सितंबर 2001 के बाद भी सम्मान यूएसडी 115/मी० टन की दर पर निर्यात किया है ।
- vi. कतर से आयात का पहुंच मूल्य पूरी उत्पादन लागत और घरेलू उद्योग के उचित बिक्री मूल्य से बहुत कम है ।
- vii. पाटित आयातों के कारण मूल्य कटान, मूल्य दमन और मूल्य संकुचन हुआ है ।
- viii. घरेलू उद्योग को भारतीय बाजार में कास्टिक सोडे की बिक्री से वित्तीय घाटा हो रहा है ।
- ix. कतर से आयात होने के कारण याचिकाकर्ता कंपनी के अनेक ग्राहक टूट गये हैं और बिक्री कम हो गयी है ।
- x. लगभग 6 महीने की छोटी सी अवधि में कतर के निर्यातक ने 10000 मी० टन से अधिक का निर्यात कर दिया है और पाटनरोधी शुल्क भूतलक्षी प्रभाव से लगाना चाहिए ।
- xi. यह खतरा कोरी कल्पना नहीं है, अपितु वास्तविक और आसन्न है क्योंकि ऐसा ज्ञात हुआ है कि निर्यात यूएसडी 115 प्रति मी० टन की दर पर किये गये हैं । पाटनरोधी शुल्क परिवर्तनीय डालर के रूप में लगाया जाना चाहिए ।
- xii. नालको के निवेदनों के जवाब में घरेलू उद्योग ने बताया है कि नालको की मांग 10000 मी० टन की है और घरेलू उद्योग गत समय में नालको की मांग पूरी करता रहा है ।
- xiii. क्षति पर नालको के तर्कों के संबंध में उल्लेखनीय है कि घरेलू उद्योग का दावा वास्तविक क्षति पर आधारित नहीं है अपितु वास्तविक क्षति के खतरे पर आधारित है ।
- xiv. जांच अवधि के दौरान उत्पादन, बिक्री की मात्रा, क्षमता उपयोग जैसे विभिन्न मापदण्डों ने गिरावट दिखायी है जबकि आयात जांच अवधि के अंत में आने शुरू हुए थे ।
- xv. भारतीय उत्पादकों ने दीर्घावधि नीति के रूप में नालको को सामान की आपूर्ति के लिए रोड टैंकरों का बेड़ा ले लिया है ताकि नालको के साथ उनका कारोबार चलता रहे । जब कभी भी आयात मूल्य अधिक हुए हैं, नालको ने बड़ी सुगमता से घरेलू उद्योग को क्रयादेश दे दिए हैं ।
- xvi. पिछले कई वर्षों से नालको सुगमतापूर्वक यह जानकारी न देने का प्रयास करती रही है कि वह आयात से कितना और घरेलू उद्योग से कितना माल लेती है ।
- xvii. क्षति निर्धारण के संबंध में जैसाकि नियम 14(घ) में भी बताया गया है, वास्तविक और संभावित दोनों निर्यातों पर ही विचार किया जाना चाहिए ।

प्रकटन के जवाब में निम्नलिखित निवेदन किए गए हैं-

- i. याचिकाकर्ता ने इस बात पर पुनः बल दिया है कि मी० क्यू वी सी का पूरा उत्पादन निर्यात के लिए ही है और वास्तविक क्षति का खतरा है क्योंकि सितंबर 2001 के बाद कीमतें गिर कर यूएसडी 115 प्र०मी० टन पर आ गयी है तथा अक्टूबर 2001 और मार्च

2002 के बीच डीजीसीआईएण्डएस के अनुसार निर्यातक ने 17000मी०ट० कास्टिक सोडा निर्यात किया है और उनका बाजार आसूचना के अनुसार निर्यातक ने 30000मी०ट० समायी निर्यात की है।

- ii. यह उल्लेख किया गया है कि इन परिस्थितियों में वास्तविक क्षति का खतरा सच और आसन्न है।
- iii. याचिकाकर्ता ने इस बात पर भी पुनः बल दिया है कि कतर से निर्यात की वृद्धि की दर काफी ऊँची है और एक वर्ष से कम समय की छोटी सी अवधि में अकेले कतर के निर्यातक का हिस्सा भारतीय मांग में 3 % हो गया है।
- iv. इसके अलावा याचिकाकर्ता ने यह भी बता है कि जांच अवधि के बाद और जून 2002 तक उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग के संबंध में मिली जानकारी अनुसार खतरा निकट ही है।
- v. यह भी बताया गया है कि सामान यूएसडी 80-115प्र०मी०ट० जितनी कम कीमत पर आयात किया गया है।
- vi. याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि कम कीमत और निर्यात मूल्यों में भारी गिरावट को देखते हुए शुल्क परिवर्तनीय डालर के आधार पर लगाया जाए।

2. निर्यातक के विचार:

- क) मै० कतर विनायल कंपनी (क्यू वी सी) लि०
- क) सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन

पाटन

- i. जांच अवधि अर्थात् 1.1.2001 से 30.9.2001 के बीच कोई आयात नहीं हुआ है और आयात 18.10.2001 के बाद ही हुआ है। निर्यातक ने जून 2001 में उत्पादन आरंभ किया था और भारत में आयात के लिए पहले सौदे पर अंततः 12.10.2001 के आसपास बातचीत हुई थी सबूत के तौर पर दिनांक 12.10.01 के इनवाइस और दिनांक 12.10.2001 के लदान बिल की सैंपल प्रति संलग्न है।
- ii. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क और धारा 9ख(ख)(i)और (ii)में यह व्यवस्था है कि जब भारत में सामान का आयात उनके सामान्य मूल्य से कम पर हो तब लेवी लगायी जा सकती है।
- iii. पाटन, क्षति, कारणात्मक संबंध और न्यूनतम का समूचा विश्लेषण जांच अवधि की सीमा में होना चाहिए और जब आयात हुआ ही न हो तब उस स्थिति में कोई विश्लेषण नहीं किया जा सकता और ऐसे में लेवी स्वतः ही फेल हो जाएगी।
- iv. सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान, आकलन उन पर पाटनरोधी शुल्क की वसूली तथा क्षति निर्धारण हेतु) नियमावली, 1995 के नियम 4(1)(क) के अधीन निर्दिष्ट प्राधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह किसी वस्तु के आयात के संदर्भ में आरोपित पाटन के अस्तित्व, डिग्री और प्रभाव की जांच करे और जब आयात हुआ ही नहीं तो यह कर्तव्य पूरा नहीं हो सकेगा। अतः पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाया जा सकता है।

- v. पाटनरोधी नियमावली के नियम 14 के अधीन जब आयात न हो और पाटन न हो तब निर्दिष्ट प्राधिकारी का काम वैधानिक शासनादेश से समाप्त हो जाता है। नियम 14(ग) और 14(घ) के अनुसार न्यूनतम मापदण्ड पूरे नहीं हो सकते।
- vi. आवेदक का यह कथन विरोधाभासी और भ्रामक है कि निर्यात शुरु हो गया और पोत शीघ्र ही पहुंचने वाले हैं और नियम 5(3)(ख) के अधीन जब सबूत सच्चा न हो तब जांच आरंभ करना ही गलत है।
- vii. प्रारंभिक जांच परिणामों में प्रोफार्मा इनवाइस के आधार पर लेवी की सिफारिश की गयी है जबकि भारतीय संविदा अधिनियम के तहत प्रोफार्मा इनवाइस से ऑफर नहीं बनती। माननीय न्यायालय के कई फैसलों का हवाला दिया गया है।
- viii. डब्ल्यू टी ओ के प्रावधानों के कुछ परोक्ष संदर्भ शासनादेशित समझौते या नियम नहीं हैं।
- ix. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 और 9 के तथा नियमावली के नियम 4, नियम 5, नियम 12 और नियम 17 सभी आयात के बारे में पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच करने और जांच परिणाम निकालने का आदेश देते हैं। यह जांच अवधि के दौरान हुए आयातों की होती है।
- x. धारा 9क(8) में अन्य बातों के साथ-साथ लेवी मुद्दे के लिए सीमाशुल्क अधिनियम 1962 के प्रावधानों को अपनाया गया है। सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 2(23) में भारत से बाहर स्थित किसी स्थान से भारत में लाने को "आयात" परिभाषित किया गया है।
- xi. पाटनरोधी समझौते में "बिक्री की तिथि" की व्यवस्था है जो केवल विनिमय दर की गणना के लिए संगत है।
- xii. गार्डन सिल्क मिल्स लि० एण्ड ए एन आर, बनाम भारत का संघ तथा अन्य 1999(113) ईएलटी 358 (एससी) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह घोषणा की थी कि आयात तब शुरु होता है जब माल सीमागत समुद्र में प्रवेश करता है और पूरा तब होता है जब सामान की निकासी भारतीय भूमि में हो जाती है।
- xiii. निवेदन यह है कि क्योंकि आयातकों/व्यापारियों ने निर्दिष्ट प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया सिर्फ इसलिए यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि उन्हें भलीभांति मालूम था कि जिस मूल्य पर सामान भारत में आयात किया जा रहा था वह पाटित मूल्य था। इसके विपरीत, आयातकों/व्यापारियों का उत्तर न देना ही उचित था क्योंकि जांच अवधि के दौरान आयात हुआ ही नहीं।
- xiv. यह पाटनरोधी प्रावधानों को पूर्णतया गलत समझना है कि आयात के किसी आरोपित खतरे को पाटन का मामला बना लेना पाटनरोधी न्याय शास्त्र का दुरुपयोग है।
- xv. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क और धारा 9 ख में पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के बारे में स्पष्टीकरण दिया है और धारा 9 तथा 9क में शुल्क नहीं लगाने के बारे में भी स्पष्टीकरण दिया गया है।
- xvi. निर्दिष्ट प्राधिकारी पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अभ्युक्ति बाध्यकारी है और आयात की घटना भी स्पष्टतया तय हो चुकी है।
- xvii. मे० क्यू वी सी निर्दिष्ट प्राधिकारी के रिकार्ड में बैलेंस शीट रखने की आज्ञा चाहते हैं।

- xviii. प्रोजेक्ट रिपोर्ट गोपनीय दस्तावेज है और निर्यातक का निजी है, निर्दिष्ट प्राधिकारी की मानक प्रश्नावली में यह अपेक्षित भी नहीं है और यदि सामान्य मूल्य निर्धारण करने के संबंध में देखें तो परियोजना रिपोर्ट नगण्य ही है ।
- xix. यूरोपीय संघ और अमेरिकी कानून के बारे में दिए गए संदर्भों के संबंध में ~~ग्राधिकारकर्ता~~ की कड़ी परीक्षा होनी चाहिए ।
- xx. सामान्य मूल्य निर्धारण के बारे में, प्रार्थी भारतीय उत्पादन लागत के आधार पर परिकलित लागत के आधार पर कार्यवाही करते हैं जबकि नियम 9(क)(ग)(ii)(ख) के अनुसार उद्गम के देश की लागत पर विचार किया जाना चाहिए ।
- xxi. कास्टिक सोडे के उत्पादन की लागत में 60 % लागत बिजली की होती है जो कि भारत में कतर ही अपेक्षा 12 गुणा मंहगी है ।
- xxii. प्राथमिक जांच परिणामों में भी भारत में परिकलित लागत के आधार पर ही कार्यवाही की गई है ।
- xxiii. क्यू वी सी द्वारा दी गयी उत्पादन लागत को अस्वीकार करने के कारण इस प्रकार हैं -
(क) बैलेंस शीट नहीं दी गयी, जैसा कि बताया जा चुका है यह संभव नहीं था क्योंकि उत्पादन जून 2001 में ही आरंभ हुआ था और जब मांगी गयी दिसम्बर/जनवरी में तब यह उपलब्ध ही नहीं थी और (ख) कुछ ने आंकड़ों के अंतर का दावा किया जो कि बहुत मामूली था और यह स्पष्ट कर दिया गया था कि समयावधि के आंकड़ों को ध्यान में रखा जाना चाहिए ।

प्रकटन विवरण के उत्तर में, निम्नलिखित निवेदन किये गये हैं-

क. पाटन

- i. आयातको ने उत्तर नहीं दिया इस बात का पाटन से कोई संबंध नहीं है जो कि निर्यात मूल्य और कतर के सामान्य मूल्य का काम है ।
- ii. यह आश्चर्यजनक है कि घरेलू उद्योग ने यह दावा किया कि कोई अगोपनीय सारांश पेश नहीं किया गया । यदि रिकार्ड कोई अगोपनीय सारांश नहीं होता तो निर्दिष्ट प्राधिकारी जांच के लिए दौरा नहीं करते ।
- iii. इस वक्तव्य के संदर्भ में आयात संगत तथ्य है न कि निर्यात । यह स्पष्ट रूप से बताया गया कि जांच अवधि के दौरान न तो निर्यात हुआ और न ही भारत में आयात हुआ ।
- iv. इस का जोरदार खंडन किया जाता है कि उत्पाद को विभिन्न शर्तों पर निर्यात किया गया माना जा सकता है जैसे कि " एक पक्की आफर/क्रयादेश और रीसेल की ऑफर आदि " यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विचारों के एकदम विपरीत है । तब तो यह और भी अधिक तर्कसंगत नहीं बैठती जब यह पता चले कि कतर में विचाराधीन उत्पाद बनाने वाला निर्माता केवल निर्यातक ही है ।
- v. यह निर्विवाद सत्य है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने रिकॉर्ड की जांच के लिए कतर का दौरा किया था जिससे यह साफ सिद्ध होता है कि उत्पादन लागत के ब्यौरे और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में यह रिकार्ड किया जाना चाहिए कि सारी अपेक्षित जानकारी ही दी जा चुकी है और कानून के अनुसार उसकी जांच भी कर ली गयी है ।

- vi. आपूर्ति अभी नहीं दी गयी है के संदर्भ में यूरोपीय संघ और अमेरिकी प्रावधानों के अनुसार इसे शुल्क लगाने के आधार के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता जबकि कोई आयात हुआ ही नहीं है। यह हो सकता है कि समग्र जांच के एक अंग के रूप में और खतरे का आकलन करने के लिए प्राधिकारी समग्र विश्लेषण के एक अंग के रूप में ऑफर आदि को देख सकते हैं। वहीं तर्क एक स्वतंत्र आफर पर लागू करना कानून में निराधार और तथ्यहीन होगा।
- vii. पाटन मार्जिन निर्धारित करने और पाटनरोधी शुल्क वसूल करने के क्षेत्राधिकार के बारे में "भ्रांति" के विषय में उल्लेखनीय है कि यह दोनों एक दूसरे से गहरा संबंध रखते हैं क्योंकि पाटन मार्जिन निर्धारण के बिना पाटनरोधी शुल्क की वसूली हो ही नहीं सकती। वास्तव में जैसा कि कानून है, पाटन रोधी शुल्क वसूलने की शक्ति तो पाटन मार्जिन निर्धारण से ही उत्पन्न होगी। इस संबंध में सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 9क असंदिग्ध है।
- viii. पाटनरोधी शुल्क भविष्यकालीन आयातों पर लगाया जा सकता है, इस तथ्य के बारे में घरेलू उद्योग ने स्वयं ही स्वीकार किया है कि भविष्य में भी पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए "निर्यात के बाद ही पाटन होगा"। इस मामले में तथ्य यही है कि जांच अवधि के दौरान कोई निर्यात या आयात नहीं हुआ है।

ख. सामान्य मूल्य

- i. सामान्य मूल्य के बारे में निवेदन है कि जब सामान्य मूल्य निर्धारण हेतु घरेलू बिक्री अपर्याप्त है तो निर्यात देश का निर्यात मूल्य एक विकल्प हो सकता है। हालांकि निर्दिष्ट प्राधिकारी का विवेकाधिकार है कि वह किसे (अर्थात् उत्पादन लागत या तीसरे देश को निर्यात मूल्य) आधार मानें किन्तु इस विवेकाधिकार का उपयोग करते समय पारदर्शिता बनाए रखना भी अत्यावश्यक है।
- ii. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने तीसरे देश की निर्यात कीमत की बजाए उत्पादन लागत को अपनाने का कोई कारण नहीं बताया है।
- iii. उल्लेखनीय है कि नव स्थापित कंपनी जब परियोजना स्तर से औद्योगिक उत्पादन में जाती है तो उसमें कई चरण होते हैं। क्यू वी सी के लिए निम्नलिखित चरण थे:-
कार्य निष्पादन जांच पूर्ण हुई..... XXX
उधारदाता विश्वसनीयता जांच पूर्ण हुई..... XXX
इंजीनियरिंग और प्रोजेक्ट पूर्ण हुए..... XXX
अतः इस प्रकार 'XXX' में वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ करने की योजना थी। वाणिज्यिक उत्पादन पर विचार करते समय निर्दिष्ट प्राधिकारी को इन तथ्यों पर भी विचार करना चाहिए।
- iv. क्योंकि क्यू वी सी आरंभिक स्तर पर ही 72 % क्षमता का उपयोग कर सका था इसका अर्थ यह नहीं है कि यह वाणिज्यिक उत्पादन का स्तर था। 72 % क्षमता उपयोग के संदर्भ में और उत्पादन लागत निर्धारित करने के लिए प्राधिकारी ने इसे आधार मान लिया, यह अत्यंत आपत्तिजनक है, क्योंकि कोई भी संयंत्र, विशेष रूप से नया संयंत्र इसलिए नहीं स्थापित किया जाता कि XXX % से क्षमता उपयोग पर चले। यह उचित और

सामान्य व्यापारिक व्यवहार है और प्राधिकारी ने इसकी अनदेखी करके संयंत्र परिचालन के अर्थतंत्र की वाणिज्यिक वास्तविकताओं का अनादर किया है। 72 % क्षमता का उपयोग करके पक्के तौर पर लाभार्जन करना संभव नहीं है।

ग. जांच अवधि में निर्यात नहीं होने के बारे में तर्क

- i. निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा डब्ल्यू टी ओ के अनुच्छेद 21 से ली गयी धारणा " देश के व्यापार में प्रवेश " बिल्कुल निराधार है। यह तथ्य कानून है कि भारत में पालिका कानून किसी भी समझौते के प्रावधानों से ऊपर होते हैं। वास्तविकता यह है कि सबद्ध धारा भारत में जांच अवधि के दौरान विचाराधीन वस्तु के आयात पर लागू होती है। इसके अलावा, दक्षिण अफ्रीका मामले सहित निर्दिष्ट प्राधिकारी ने जिन मामलों पर भरोसा किया है निर्यात कीमत निकालने के लिए टेंडर मूल्य पर विचार किया है किन्तु निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा सदर्थित किसी भी मामले में टेंडर मूल्य पर भरोसा नहीं किया है। साथ ही वर्तमान मामले की एक वास्तविकता यह भी है कि जांच अवधि के दौरान ऐसा कोई टेंडर नहीं खुला जिस पर बाद में आपूर्ति की गयी हो।

ख. क्षति, कारणात्मक संबंध और अन्य मुद्दे:

- i. जांच अवधि के बाद अक्टूबर में हुए सारे आयात एडवांस लाइसेंस के तहत थे और जांच अवधि के दौरान क्षति नहीं पहुंचा सकते।
- ii. आवेदन और प्राथमिक जांच परिणामों में वास्तविक क्षति के खतरे को आधार मानकर चला गया है। अनुबध्द II के पैरा (viii)सहित नियम 11(2) के प्रावधानों पर भरोसा किया गया है।
- iii. वास्तविक क्षति के खतरे को आधार मानकर की गयी कार्यवाही पूर्णतया काल्पनिक और अधिकार क्षेत्र से बाहर की है। यदि वास्तविक क्षति का खतरा भी हो तब भी आधारभूत पूर्व-शर्तें तो पूरी होनी ही चाहिए और यहाँ जांच अवधि के दौरान आयात हुआ ही नहीं।
- iv. अनुबध्द- II के पैरा (vii)में संगत तरीके से अर्थ लगाया गया है कि जांच अवधि के दौरान पाटित आयात अवश्य होने चाहिए और जब जांच अवधि के दौरान कोई क्षति न हो, वास्तविक क्षति का खतरा होना और आसन्न होना अनिवार्य है। जब जांच अवधि में पाटन न हो तब वास्तविक क्षति के खतरा का मामला पोषणीय आधार पर नहीं बन सकेगा।
- v. याचिकाकर्त्ता बहु-उत्पाद कंपनी है और इसे क्लोरीन बनाने में बड़ा भारी लाभ हो रहा है तथा निर्दिष्ट प्राधिकारी को याचिकाकर्त्ता के इस दावे की जांच करनी चाहिए कि उन्हें हानि हो रही है।

प्रकटन विवरण के उत्तर में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :-

वास्तविक क्षति के खतरे के मुद्दे के संबंध में

- i. नियम 11 और नियमों के अनुबध्द II के पैरा (vii)के साथ पटित 9ख(ii)के अंतर्गत ऐसे प्रावधान हैं जिनमें वास्तविक क्षति के खतरे को विनिर्दिष्ट किया गया है जिन सभी उपबध्दों में इस बात पर जोर दिया गया है कि (जांच अवधि के भीतर) पाटन होना

चाहिए और इस पाटन से वास्तविक क्षति का आसन्नवर्ती खतरा उत्पन्न होना चाहिए ।

इसका पैरा (viii) में उल्लेख किया गया है जो निम्नानुसार है

परिस्थितियों में ऐसे परिवर्तन, जिसमें कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जिसमें पाटन से क्षति होगी, का स्पष्ट रूप से अनुमान लगाया जाना चाहिए और उसे आसन्नवर्ती होना चाहिए ।"

- ii. वास्तविक क्षति के खतरे के इस प्रावधान से निम्नलिखित की पुष्टि करने की मूलभूत पूर्व शर्तों को पूरा करने की अनिवार्य जरूरतों में कमी अथवा उनकी उपेक्षा नहीं होती है ।
 - (i) पाटन
 - (ii) आधार
 - (iii) न्यूनतम सीमा
- iii. विश्लेषण अवधि (जांच अवधि) के दौरान ऐसी स्थिति में जहां जांच अवधि के दौरान कोई आयात न हुए हों, लेवी हेतु अनिवार्य पूर्व शर्त की पूर्ति नहीं होती है । वास्तविक क्षति के खतरे के आधार पर किसी कार्रवाई में इन अनिवार्य पूर्व शर्तों की उपेक्षा नहीं की जा सकती । वर्तमान मामले में सत्यापन के बारे में किए गए दौरे के दौरान जांचाधीन उत्पाद हेतु दीर्घावधि संविदा की एक सूची प्रस्तुत की गई थी जिसमें अन्य तीसरे देशों के लिए कुल उत्पादन का XXX % शामिल था जिस पर निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा स्पष्ट रूप से विचार किया जाना चाहिए ।
- iv. अनुबंध II के पैरा (vii) में सुसंगत परिकल्पना के अनुसार जांच अवधि में आयातों का पाटन होना चाहिए और भले ही जांच अवधि में कोई क्षति न हुई हो । वास्तविक क्षति का खतरा जांच अवधि के बाद भी बना रहना चाहिए और उसे आसन्नवर्ती होना चाहिए । जांच अवधि में पाटन के बिना वास्तविक क्षति के खतरे का कोई उचित मामला नहीं बन सकता ।
- v. अतः अनुरोध है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी अमेरिका से हाइ फ्रक्टोस कार्न सिर्फ (एचसीएफएस) की मैक्सिको-पाटनरोधी जांच के मामले में पैनल की रिपोर्ट द्वारा पैरा 7.131 में दिए गए निर्णय का अनुपालन करें जिसमें पैनल के समक्ष यू एस ए ने यह दावा किया था कि क्षति के खतरे का निर्धारण पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3.7 में निर्धारित कारकों की जांच मात्र के आधार पर नहीं किया जा सकता । क्षति के खतरे के निर्धारण के लिए अनुच्छेद 3.4 में निर्धारित संगत आर्थिक कारकों की जांच के जरिए घरेलू उद्योग पर आयातों के प्रभाव का आकलन करना भी अपेक्षित होता है । अनुच्छेद 3.7 में इस बात का निर्धारण अपेक्षित है कि क्या वास्तविक क्षति होगी, अनुच्छेद 3.1 में यह अपेक्षित है कि क्षति के खतरे सहित क्षति के निर्धारण में आयातों के प्रभाव की जांच शामिल होती है और अनुच्छेद 3.4 में वे कारक निर्धारित किए गए हैं जिन पर घरेलू उद्योग पर आयातों के प्रभाव की जांच करते समय अन्य संगत कारकों के साथ-साथ विचार किया जाना चाहिए । इस प्रकार हमारे विचार से पाटनरोधी करार के पाठ में खतरे के निर्धारण हेतु अनुच्छेद 3.4 के कारकों पर विचार करना अपेक्षित है । अनुच्छेद 3.7 में ऐसे अतिरिक्त कारक निर्धारित किए गए हैं जिन पर खतरे के मामले में विचार किया

जाना चाहिए किन्तु उसमें अनुच्छेद 3.4 की अपेक्षाओं के अनुसार घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करने की अनिवार्यता समाप्त नहीं की गई है।

क्षति के मुद्दे के संबंध में

- i. नियमावली के अनुबंध II में यह अनिवार्य बनाया गया है कि क्षति के निर्धारण के प्रयोजनार्थ " उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों के मूल्यांकन की तब तक जांच की जानी चाहिए जब तक आपवादिक परिस्थितियाँ न हों और अन्य सकारात्मक संकेतकों की उपेक्षा करते हुए कुछेक आर्थिक नकारात्मक संकेतकों के संबंध में क्षति के मुद्दे के निर्धारण को केवल तय करना संभव नहीं है।"
- ii. यूरोपीय आयोग के मामले में - भारत से काटन टाइप बैग लिनेन के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क - पैनल की रिपोर्ट - डब्ल्यू टी/डीएस 141/आर के पैरा 6.154 के अनुसार अनुच्छेद 3.4 के अंतर्गत इस प्रावधान का साधारण अर्थ यह है कि पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में पाटनरोधी डब्ल्यू टी ओ करार के पैरा 3.4 में सूचीबद्ध समस्त कारकों का मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। बैग लिनेन मामले में भारत ने बताया था कि क्षति संबंधी समस्त संगत कारकों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। अतः पैनल का निष्कर्ष यह था कि " इस वाक्यांश के प्रयोग से " अनुच्छेद 3.4 में यह शामिल होगा कि उक्त प्रावधानों में सूचीबद्ध कारकों के मूल्यांकन की उचित व्याख्या को सभी मामलों में अनिवार्य बना दिया गया है।
- iii. अतः चूंकि क्षति के समस्त कारकों की उपर्युक्त व्याख्या के मूल्यांकन का सुझाव भारत द्वारा दिया गया था और उसे पैनल द्वारा स्वीकार किया गया था इसलिए निर्दिष्ट प्राधिकारी का यह दायित्व बन जाता है कि वह क्षति संबंधी सभी मापदण्डों पर विचार करें यद्यपि इसके साथ ही साथ प्रारंभिक जांच परिणामों में यह भी स्वीकृत दृष्टिकोण है जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती कि:
 - (i) बिक्री, पूंजी उपयोग, उत्पादन, निवल बिक्री प्राप्ति और मांग जैसे समस्त संकेतकोंमें वृद्धि हुई है।
 - (ii) आयातों में कमी आई है।
 - (iii) क्षति संबंधी समस्त मापदण्ड सकारात्मक है।
- iv. इस प्रकार जांच अवधि में स्पष्ट रूप से कोई क्षति नहीं हुई है। यह प्रासंगिक है कि घरेलू उद्योग के लिए एक वर्ष तक पाटनरोधी शुल्क उपलब्ध किया गया है जिससे घरेलू उद्योग को हुई कोई वास्तविक क्षति समाप्त हो गई है। उपर्युक्त कारणों से अन्य बातों के साथ यह सिद्ध हो जाता है कि कोई कारणात्मक संबंध नहीं है।

ख. कतर राष्ट्र का दूतावास, नई दिल्ली

- (i) कतर राष्ट्र के दूतावास ने अनुरोध किया है कि जांच परिणाम डब्ल्यू टी ओ में सहमत सिद्धांतों एवं क्रियाविधियों के अनुसार निकाले जाने चाहिए।

3. आयातकों के विचार

मै. नेटीनल अल्मुनियम कंपनी लि. (नाल्को) का विचार

(क) सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत तथा पाटन

पाटन

- i) जांच अवधि के दौरान मै. क्यू वी सी से आयात नहीं हुआ है। लदान संबंधी बिल तथा दूसरे सामग्री से इंगित होता है कि अक्टूबर 2001 में निर्यात हुआ है। भारत में वस्तुओं के वास्तविक आयातों से पाटन नहीं हो सकता है तथा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1995 की धारा 9(क)(i) के अनुसार इस पर शुल्क नहीं लगाया जा सकता है। नियम 4(i)(क) के अनुसार भी चूंकि आयात नहीं हुआ है पाटन की मौजूदगी नहीं हो सकता है और इसलिए पाटन की मात्रा या प्रभाव की जांच नहीं की जा सकती है।
- ii) आयात शब्द को सीमा शुल्क अधिनियम में परिभाषित किया गया है और इसका अर्थ है सीमाशुल्क चौकियों से वस्तुओं को वास्तविक रूप से लाना।
- iii) धारा 9(क)(i)(ख) में निर्यात कीमत को परिभाषित किया गया है तथा इसका विशेष अर्थ निर्यातित देशों में निर्यातित वस्तु का कीमत से है।
- iv) माल का वास्तविक आयात पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए पूर्व शर्त है।
- v) पेशकश अथवा प्रोफार्मा बीजक एक निर्णीत संविदा नहीं है और इस संबंध में न्यायालयों के विभिन्न निर्णय हैं। प्रोफार्मा बीजक भी पूर्णतया असंगत है क्योंकि बीच समुद्र में बिक्री की जा सकती है जिससे माल किसी अन्य देश को भेजा जा सकता है ताकि उसे आयात न कहा जा सके।
- vi) पी एस एफ के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यह नहीं स्वीकारा कि मैसर्स रियायंस द्वारा बाद में किए गए आयातों से संबंधित बीजक जांच अवधि के भीतर का था और वास्तविक आयात जांच अवधि के बाद हुआ।
- vii) घरेलू उद्योग और निर्यातक दोनों की उत्पादन लागत से संबंधित सूचना का खुलासा नहीं किया गया है और यह प्राकृतिक न्याय को न मानना है। याचिकाकर्ताओं की उत्पादन लागत पर विचार करते समय इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि इलेक्ट्रो कैमिकल यूनिट (ई सी यू) वसूली कीमत महत्वपूर्ण है।
- viii) प्रारंभिक जांच परिणामों में सामान्य मूल्य और समायोजनों से संबंधित अधिकांश सूचना गोपनीय रखी गयी है और नाल्को ने यह निवेदन किया है कि प्राकृतिक न्याय और रक्षा के प्रयोजनार्थ उसे सभी सामग्री प्रदान की जानी चाहिए।
- ix) कतर जैसे विदेश में कास्टिक सोडा की उत्पादन लागत का परिकलन करते समय कलोरीन के उत्पादन और कलोरीन की बिक्री वसूली पर विचार करना आवश्यक है जैसाकि मौखिक साक्ष्य के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा यह स्वीकारा गया है कि विदेशों में कलोरीन मुख्य उत्पाद है, कास्टिक सोडा उप उत्पाद है।
- x) प्राधिकारी को इस तथ्य पर विचार करना चाहिए कि निर्यातक पाटनरोधी शुल्क लगाने के प्रयोजनार्थ सामान्य मूल्य से कम कीमत पर बिक्री कर रहा है।

ख. क्षति कारणात्मक संबंध और अन्य मुद्दे

- i) नगरपालिका कानून की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय कानून की व्याख्या से संबंधित विभिन्न निर्णयों जैसकि उचित विचार करने के लिए नाल्को द्वारा सूचित किया गया है ।
- ii) नाल्को ने भी यह निवेदन किया है कि धारा 12 के अनुसार प्रारंभिक जांच परिणामों से पूर्व बचाव के प्रयोजनार्थ एक सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए और यह कि यह प्रारंभिक निष्कर्षों से पहले सुनवाई पूर्व निर्णय होना चाहिए जिसका नियमों में उल्लेख किया गया है और यह सुनवाई पश्चात् का निर्णय नहीं होना चाहिए ।
- iii) साथ ही नियमों में प्रारंभिक निष्कर्षों से पहले सुनवाई शामिल है ।
- iv) विद्युत लागत की वजह से कतर में उत्पादन की लागत काफी कम है और पाटन नहीं हो सकता है ।
- v) नियमों एवं अधिनियमों में अनुमानों की अनुमति नहीं दी गई है किन्तु यह प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य होने चाहिए कि पाटन हो रहा और दूसरे इससे घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है ।
- vi) भारत में कास्टिक सोडा की कीमत माल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत के अनुसार रही है और इसका आयातित माल की कीमत से कोई लेना-देना नहीं है ।
- vii) नाल्को ने अपनी आपूर्ति की जरूरतों के लिए कास्टिक सोडा लाइ की आपूर्ति हेतु निविदाएं आमंत्रित की थीं । कास्टिक सोडा की वर्तमान 2 लाख मीटन की जरूरत (1 लाख मी.टन सुखा कास्टिक सोडा) के स्थान पर भारतीय विनिर्माताओं ने नाल्को की जरूरत की मात्रा से काफी कम मात्रा प्रदान की है जिससे नाल्को के लिए यह अनावश्यक रूप से महंगा हो गया है ।
- viii) आपूर्तियां ट्रकों द्वारा की जाती है जो केवल 10 मी.टन ही ले जाते है जबकि नाल्को द्वारा की गई सामान्य पोत लदान 5000 मी.टन की सीमा में है । घरेलू आपूर्तिकर्ताओं द्वारा की गई आपूर्तियां विदेशी आपूर्तिकर्ताओं की तुलना में लघु मात्रा में हैं और यह कि नाल्को को पहुंच लागत भारतीय आपूर्तिकर्ताओं के मामले में अधिक है । इससे नाल्को के निर्यात और भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धात्मकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ।
- ix) प्रारंभिक निष्कर्षों में मौखिक गलतियां हैं । विश्लेषण से पता चलता है कि कोई क्षति नहीं हुई है । यह मालूम हुआ है कि घरेलू बिक्रियां, क्षमता उपयोग, निवल बिक्री वसूली में वृद्धि हुई है और यह कि आयातों में गिरावट आई है जांच अवधि के दौरान कोई आयात नहीं हुआ है तथा यह कि मांग में वृद्धि हुई है । अतः ये सभी कारक यह प्रदर्शित करते हैं कि घरेलू उद्योग को

क्षति हुई है। प्राधिकारी ने यह मानने में मनमानी की है कि जांच अवधि में निवल बिक्री वसूली नुकसान रहित कीमत से नीचे रही है। यह स्पष्ट नहीं है कि नुकसान रहित कीमत कैसे परिकलित की है।

x) निवल बिक्री वसूली में कलोरीन से हुई वसूली को शामिल नहीं किया गया है।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

निर्यातक तथा याचिकाकर्ता द्वारा किए गए पूर्वोक्त अनुरोधों की उस सीमा तक जांच की गई है, उन पर विचार किया गया है, जिस सीमा तक ये नियमानुसार संगत हैं और मामले पर प्रभाव डालते हैं, और इन जांच परिणामों में समुचित स्थानों पर उन पर कार्रवाई की गई है।

1. याचिकाकर्ता की स्थिति, विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

प्राधिकारी यह बात नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद, समान वस्तु और घरेलू उद्योग की स्थिति के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया गया है। अतः प्राधिकारी दिनांक 18.1.2002 के प्रारंभिक जांच परिणामों में यथा इंगित इन पहलुओं पर निष्कर्षों की पुष्टि किए जाने का प्रस्ताव करते हैं।

क) विचाराधीन उत्पाद

प्राधिकारी दिनांक 18.1.2002 के प्रारंभिक निष्कर्षों में विचाराधीन उत्पाद के बारे में पैरा ग.1 का स्मरण करते हैं और इसकी पुनरावृत्ति करते हैं।

वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद कतर के मूल का अथवा वहां से निर्यातित सोडियम हाइड्रोक्साइड (रासायनिक नाम एन ए ओ एच), है जिसे आम तौर पर कास्टिक सोडा के रूप में जाना जाता है। कास्टिक सोडा एक अकार्बनिक, झागदार तीखा अल्कालिन और गंधहीन रसायन है और इसका प्रयोग लुग्दी एवं कागज, अखबारी कागज, विस्कोज यार्न, स्टेपल फाइबर, एल्युमीनियम, काटन, टेक्सटाइल, टॉयलेट और लांड्री साबुन, डिटरजेंट, रंजक, औषध एवं भेषज में विनिर्माण, पेट्रोलियम शोधन इत्यादि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है।

कास्टिक सोडा सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 28, सीमाशुल्क शीर्ष 2815.11 और 28.12 के तहत वर्गीकृत है। आई टी सी 8 अंकीय वर्गीकरण के अनुसार यह उत्पाद सीमाशुल्क शीर्ष 2815.1101, 2815.1102 और 2815.1200 के तहत वर्गीकृत है तथापि, यह वर्गीकृत केवल सांकेतिक है और यह वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी रूप में बाध्यकारी नहीं है।

कास्टिक सोडा का उत्पादन तीन तकनीकें अर्थात् मर्करी सेल प्रक्रिया, डायाफ्रेम प्रक्रिया और मेम्ब्रेन प्रक्रिया द्वारा दो रूपों अर्थात् सज्जीदार पानी और ठोस रूप में किया जाता है।

कास्टिक सोडा का आयात ओ जी एल के तहत किया जा सकता है और इस पर 35 प्रतिशत का मूल सीमाशुल्क लगता है। वर्तमान जांच में कास्टिक सोडा के सभी स्वरूप शामिल हैं।

प्राधिकारी किसी निवेदन न होने की स्थिति में इसकी पुष्टि करते हैं ।

ख) समान वस्तु

प्राधिकारी दिनांक 18.1.2002 के प्रारम्भिक निष्कर्षों में समान वस्तु के बारे में पैरा ग.2 का निम्नानुसार स्मरण करते हैं और इसे दोहराते हैं-

प्राधिकारी यह बात नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता ने यह दावा किया है कि उनके द्वारा उत्पादित वस्तु संबद्ध देश में उत्पादित और वहां से निर्यातित वस्तु के समान वस्तु है । दोनों वस्तुएं तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय भी हैं और उपभोक्ता घरेलू रूप से उत्पादित तथा आयातित वस्तु का उपयोग एक दूसरे के स्थान पर कर रहे हैं । यह उल्लेख किया गया है कि कास्टिक सोडा का प्रसंस्करण विश्व भर में तीन प्रक्रियाओं अर्थात् मर्करी सेल प्रक्रिया, डायाफ्रेगम प्रक्रिया और मेम्ब्रेन प्रक्रिया द्वारा किया जाता है । इन प्रक्रियाओं में अंतर का तात्पर्य विभिन्न विशेषताओं के संबंध में उत्पाद में अंतर से नहीं है । इसके अलावा, तीनों प्रक्रियाओं के लिए उत्पादन लागत में कोई खास अंतर नहीं है । याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उनके द्वारा उत्पादित वस्तु और कतर से निर्यातित वस्तु नियमों के अर्थ के भीतर समान वस्तु हैं ।

प्राधिकारी यह बात नोट करते हैं कि कतर के निर्यातक ने यह अनुरोध किया है कि याचिकाकर्ताओं ने लागत और विनिर्माण प्रक्रियाओं के बारे में कुछ अनुमान लगाए हैं । निर्यातक ने यह उल्लेख किया है कि उनकी समझ के अनुसार तीनों विनिर्माण प्रक्रियाओं में से प्रत्येक के लिए बिजली की खपत में पर्याप्त अंतर है और इस प्रकार प्रत्येक प्रक्रिया में अंतरग्रस्त लागत भी भिन्न-भिन्न हैं । निर्यातक द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि भारतीय उत्पादकों के पास क्लोरिन के उचित स्थान नहीं है और यह कि वे क्लोरिन को गैर व्यापार योग्य वस्तु मानते हैं और इस प्रकार यह कास्टिक सोडा के उत्पादन के समय बनने वाला सह उत्पाद है । निर्यातक ने यह बताया है कि उनके मामले में क्लोरीन मुख्य कच्ची सामग्री है और इसे सह-उत्पाद नहीं मानते हैं । वस्तुतः कास्टिक क्लोरीन के उत्पादन के समय बनने वाला सह उत्पाद है ।

उपरोक्त अनुरोधों को नोट करने के बाद प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि हालांकि मै. क्यू वी सी कतर निर्यातक ने तीनों प्रक्रियाओं के लिए लागतों में अंतर का संकेत दिया है तथापि, उनके द्वारा निर्यातित उत्पाद और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद की विशेषताओं में किसी अंतर के बारे में कोई तर्क नहीं दिया गया है । निर्यातक द्वारा इस आशय का भी कोई दावा नहीं किया गया है कि उनके निर्यातित वस्तु और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु प्रतिस्थापनीय नहीं हैं । मै. क्यू वी सी द्वारा निर्यातित वस्तु के भारत में ग्राहकों द्वारा सामान्य ग्राहक होने के नाते निर्यातित वस्तु और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु का एक दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल किया गया है ।

हितबद्ध पक्षकारों से कोई निवेदन प्राप्त न होने की स्थिति में प्राधिकारी इसकी पुष्टि करते हैं और यह मानते हैं कि नियम 2 (घ) के अनुसार घरेलू रूप से उत्पादित वस्तुएं और मै. क्यू वी सी द्वारा निर्यातित वस्तुएं समान हैं ।

ग) घरेलू उद्योग की स्थिति

प्राधिकारी दिनांक 18.1.2002 के प्रारंभिक निष्कर्षों में घरेलू उद्योग की स्थिति के बारे में पैरा ग.2 का स्मरण निम्नानुसार करते हैं-

यह याचिका घरेलू उद्योग की ओर से मै. अल्काली मैन्युफैक्चरर्स एसो, इंडिया द्वारा दायर की गई है। याचिका का समर्थन मै.डी सी डब्ल्यू लि., मुंबई, मै. गुजरात अल्कालीज एंड कैमिकल्स लि., गुजरात मै. सर्च केम इंड, लि., मुंबई, मै. ग्रेसिम इंड लि., मध्य प्रदेश और मै. इण्डियन रेयन एंड इंड, लि., गुजरात द्वारा किया गया है। किसी भी घरेलू उत्पादक ने याचिका का विरोध नहीं किया है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जिन पांचों घरेलू उत्पादकों ने याचिका का समर्थन किया है उनका हिस्सा कुल घरेलू उत्पादन का 32.6% बनता है और इसलिए उनके पास पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(क) और (ख) के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से याचिका दायर करने का आधार है। जांच शुरुआत के बाद मै. सिएल कैमिकल्स कम्पलैक्स, पाटियाला, पंजाब, मै. बिहार कास्टिक एंड केमिकल्स लि. बिहार, मै. जयश्री केमिकल्स लि., उड़ीसा और मै. आंध्र प्रदेश सुगर्स लि., सगोन्डा युनिट ने भी याचिका का समर्थन किया है और क्षति संबंधी सूचना प्रस्तुत की है।

प्राधिकारी यह बात नोट करते हैं कि किसी घरेलू उत्पाद ने याचिका का विरोध नहीं किया है इसलिए प्राधिकारी निवेदन करने की स्थिति में घरेलू उद्योग की स्थिति की पुष्टि करते हैं और यह मानते हैं कि याचिकाकर्ता नियम 5(क) और (ख) के अनुसार शर्त करते हैं और नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व करते हैं।

2. पाटन मार्जिन

क) सामान्य मूल्य

प्राधिकारी प्रकटीकरण विवरण में सामान्य मूल्य के बारे में की गई टिप्पणियों का स्मरण करते हैं कि मैसर्स कतर विनील कंपनी (क्यू वी सी) ने यह दर्शाया था कि उनके देश में संबद्ध वस्तु की कोई घरेलू बिक्री नहीं हुई है। यह भी दर्शाया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा मै. क्यू वी सी के लिए दर्शाया गई परिकलित उत्पादन लागत सही नहीं है और परियोजना रिपोर्ट की कोई संगतता नहीं है जहां तक निर्यातक का प्रश्नावली के उत्तर का संबंध है। निर्यातक ने यह भी दर्शाया है कि भारत और कतर में बिजली की लागत में काफी अंतर है जो कास्टिक सोडा के उत्पादन के लिए एक प्रमुख संघटक है।

विभिन्न हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त निवेदनों को नोट करने के पश्चात् प्राधिकारी ने 10 और 11 सितम्बर, 2002 को निर्यातक का मौके पर सत्यापन किया था और निर्यातक द्वारा प्रदत्त निवेदनों और आकड़ों का अवलोकन करते समय हितबद्ध पक्षों की चिंताओं पर उचित विचार किया था। सामान्य मूल्य के निर्धारण के बारे में घरेलू उद्योग और निर्यातक द्वारा किए गए विभिन्न निवेदनों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी ने दोहा कतर में 10 और 11 सितम्बर, 2002 सत्यापन टीम द्वारा निर्यातक के अभिलेखों का मौके पर सत्यापन के दौरान इस प्रकार सत्यापित सामान्य मूल्य के लिए मैसर्स क्यू वी सी की उत्पादन लागत का संदर्भ देने का प्रस्ताव किया था।

प्राधिकारी ने प्रकटीकरण में यह संकेत दिया था कि दोहा में मैसर्स क्यू वी सी के सत्यापन के दौरान यह देखा था कि जाँच अवधि के दौरान संबद्ध माल की कोई घरेलू बिक्री नहीं की गई थी। निर्यातक ने यह संकेत दिया था कि उनकी शेयर धारक कंपनी अर्थात् मैसर्स क्यू ए पी सी ओ को बहुत की कम मात्रा में कुछ बिक्री की गई थी किन्तु वह बाजार कीमत पर नहीं थी। प्राधिकारी ने इन निवेदनों और इस प्रकार सत्यापित आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए, मैसर्स क्यू वी सी के लिए जाँच अवधि के दौरान संबद्ध माल की उत्पादन लागत *** डालर/मी.टन का संदर्भ देने का प्रस्ताव किया था और उचित लाभ मार्जिन के साथ सामान्य मूल्य *** डालर/मी.टन के रूप में आकलित किया गया है। प्राधिकारी यह बात नोट करते हैं कि जाँच के दौरान निर्यातक ने यह संकेत दिया था कि जाँच अवधि के दौरान वे 72% की क्षमता उपयोग पर प्रचालन कर रहा था जो एक परीक्षण उत्पादन की अवस्था में था न कि वाणिज्यिक उत्पादन। प्रकटीकरण में प्राधिकारी ने यह पाया था कि इस प्रकार के क्षमता उपयोग के स्तर को परीक्षण उत्पादन नहीं कहा जा सकता है और यह कि जाँच अवधि के दौरान वास्तविक उत्पादन लागत पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करने लिए विचार किया जाना है और इसलिए जाँच अवधि के दौरान वास्तविक उत्पादन के आधार पर उत्पादन लागत और सामान्य मूल्य पर विचार करने का संकेत दिया था।

प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यातक द्वारा यह इंगित किया गया है कि जाँच अवधि के दौरान के उत्पादन का 72% दर असल केवल परीक्षण उत्पादन था तथा संयंत्र का डिजाइन ऐसा है कि 72% को केवल परीक्षण उत्पादन कहा जा सकता है निर्यातक द्वारा यह भी संकेत किया गया है कि यह स्पष्ट नहीं है कि प्राधिकारी ने तीसरे देश के निर्यातों को सामान्य मूल्य के आधार के रूप में संदर्भित क्यों नहीं माना है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने पहले ही अपने सामान्य मूल्य के बारे में किए गए अनुरोधों को दोहराते हुए यह संकेत किया है कि प्राधिकारी की गई जाँच को ध्यान में रखते हुए जाँच परिणामों की पुष्टि कर सकते हैं। प्राधिकारी उक्त अनुरोधों को नोट करने के पश्चात् दोहराते हैं कि जाँच अवधि के दौरान, जिस पर विचार किया गया है, उत्पादन की वास्तविक लागत के आंकड़े ही प्रासंगिक हैं और जिन पर इसलिए सामान्य मूल्य के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ विचार किया गया है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि निर्यातक की तत्काल जाँच के दौरान जाँच अवधि के दौरान विभिन्न देशों को किए गए निर्यातों के संदर्भ में भी आंकड़ों का संदर्भ दिया गया है। तथापि तीसरे देशों के निर्यातकों का हवाला देने के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यात की मात्रा की दृष्टि से एशिया क्षेत्र में उचित तीसरा देश मलेशिया हो सकता है। जाँच अवधि के दौरान मलेशिया की प्रतिनिधि कार्यक्षम और असाधारण व्यापार निर्यात कीमत भी निर्यात के लिए इसी प्रकार परिकलित सामान्य मूल्य से सहसंबंधित होती है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि यदि परियोजना रिपोर्ट के अनुसार कथित परियोजित क्षमता उपयोगिता का भी संदर्भ दिया जाता है तो उचित लाभ परियोजना रिपोर्ट में परिकलित लाभ होगा। एफओबी पर परियोजित लाभ स्तर पर मूल्यांकन किया गया सामान्य मूल्य भी प्राधिकारी द्वारा परिकलित सामान्य मूल्य से सहसंबंधित होगा। अतः प्राधिकारी नोट करते हैं कि जाँच अवधि के दौरान उत्पादन की वास्तविक लागत के आधार पर परिकलित सामान्य मूल्य सत्य है क्योंकि ये तीसरे देशों के निर्यातों के आंकड़ों के साथ ठीक ढंग से सुमेलित होते हैं और परियोजना रिपोर्ट के अनुसार समान हैं।

इसलिए प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य को *** डालर/मी० टन प्रमाणित किया है।

(ख) निर्यात कीमत

प्राधिकारी स्मरण करते हैं कि प्रकटन में यह इंगित किया गया था कि निर्यातक ने जाँच अवधि के दौरान अनुबंधित सीआईएफ निर्यात कीमत प्रस्तुत की है और तत्पश्चात जाँच अवधि से बाहर इसके अनुकरण में की गई आपूर्तियाँ *** डालर/मी० टन पर बताई हैं। निर्यातक ने समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, मै० अटॉकिना को मार्केटिंग शुल्क, ऋण लागत तथा पत्तन खर्चों पर सीआईएफ कीमत संबंधी विभिन्न समायोजनों के क्रमशः ****, ****, ****, **** और **** की सीमा तक होने के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं।

विभिन्न समायोजनों के आधार पर कारखाना द्वार पर निर्यात कीमत के **** डालर/मी० टन माने जाने का प्रस्ताव किया है। प्राधिकारी ने इस संबंध में कोई अनुरोध न होने की दृष्टि से कारखाना द्वार पर निर्यात कीमत के **** डालर/मी० टन की पुष्टि करने का प्रस्ताव करते हैं।

ग. अन्य असहयोगी निर्यातक/उत्पादक

अन्य असहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों के संबंध में इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कोई घरेलू बिक्री नहीं हुई है और यह कतर में मै० क्यूवीसी के लिए भी संगत होगी, प्राधिकारी ने प्रकटन में मै० क्यूवीसी के लिए यथा निर्धारित सामान्य मूल्य को इन निर्यातकों/उत्पादकों के लिए नगर्न का प्रस्ताव किया था।

कारखाना द्वार पर निर्यात कीमत के संबंध में, प्राधिकारी ने असहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए निर्यात कीमत पर अंतर्देशीय भाड़े के कारण समायोजन की अनुमति देने का प्रस्ताव किया है जिससे कारखाना द्वार पर निर्यात कीमत *** डालर/मी० टन परिगणित होती है। प्राधिकारी ने अनुरोधों के न होने को ध्यान में रखते हुए कारखाना द्वार पर निर्यात कीमत के **** डालर/मी० टन होने की पुष्टि करते हैं।

उपरोक्त के आधार पर, पाटन मार्जिन **** डालर/मी० टन (47%) परिकलित होता है।

3. पाटन - सामान्य मूल्य एवं निर्यात कीमत की तुलना

प्राधिकारी स्मरण करते हैं कि प्रकटन विवरण में उन्होंने विभिन्न हितबद्ध पक्षों के जाँच अवधि के दौरान मै० क्यूवीसी को निर्यात नहीं किये जाने के संबंध में विचारों को इंगित किया था। प्राधिकारी ने पाटन की परिभाषा के बारे में निर्यातक द्वारा किए गए अनुरोधों की ओर इंगित किया था, जिसमें आयात एवं "अनुबंध" शब्दों के बारे में संगत सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का उद्धरण दिया गया था और पाटन के प्रभाव के मूल्यांकन के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी के कर्तव्यों के संबंध में नियमों की स्थिति भी बताई। निर्यातक द्वारा यह भी इंगित किया गया था कि जाँच अवधि के दौरान आयात/निर्यात न होने को ध्यान में रखते हुए, पाटन का कोई प्रभाव नहीं है और इस संबंध में आगे परीक्षण लागू नहीं हो सकते हैं। इस संबंध में प्राधिकारी ने ईयू और यूएस की प्रक्रियाओं के बारे में घरेलू उद्योग के अनुरोधों को नोट किया था। प्राधिकारी ने यह भी नोट किया था कि डेनमार्क से कैटेलिस्ट की पाटनरोधी जाँच के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एक निर्णय अनुमोदित किया गया है, प्राधिकारी स्पष्ट रूप से ये मानते हैं कि पाटन मार्जिन की तुलना बिक्रियों के लिए की जानी है न कि आयातों के लिए।

प्राधिकारी ने इस अनुरोध को भी नोट किया कि उन्होंने इस मामले में सुस्पष्ट: यह इंगित किया था कि कीमत अनुबंध ही कीमत कटौती का कारण होती है और जाँच अवधि से बाहर की गई आपूर्तियों का कोई प्रत्यक्ष महत्व नहीं था। प्राधिकारी ने नोट किया कि उन्होंने पूर्व के विभिन्न निर्धारणों जिनमें डेनमार्क से कैटेलिस्ट, ईयू सिंगापुर, थाइलैण्ड, जापान, ब्राजील एवं कोरिया आर०पी० से पीआईबी, आस्ट्रिया, चैक गणराज्य, रूस एवं यूक्रेन से सीमलैस ट्यूब्स शामिल हैं में निर्यात कीमत के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ और तत्पश्चात् पाटनरोधी शुल्क की लेवी के प्रयोजनार्थ भी निविदा कीमतों के पहलू पर विचार किया है। प्राधिकारी ने यह भी नोट किया है कि दक्षिण अफ्रीका ने भी भारत के विरुद्ध एयटबायोटेक्स के एक मामले में निर्यात कीमत के निर्धारण के प्रयोजनार्थ निविदा कीमतों पर विचार किया था। पाटनरोध पर डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद-2.1 के पठन में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन के आधारभूत सिद्धांतों के रूप में उस देश के वाणिज्य में वस्तुओं को लाना इंगित किया गया है। इस तथ्य को देखते हुए कि संविदा/निविदा कीमत जब उद्धृत हुई तो कीमतों में कटौती हुई और ये वास्तव में लदान के रूप में परिवर्तित हुई जिससे क्षति हुई यद्यपि तब भी जाँच अवधि से बाहर पाटित वस्तुएं भेजी जा सकती हैं। अतः प्राधिकारी नोट करते हैं कि मै० क्यूवीसी के मामले में, सितम्बर, 2001 के दौरान अर्थात् जाँच अवधि में एक आयातक के साथ एक साख पत्र (एलसी) खोला गया और पत्राधार जिससे यह निष्कर्ष निकला कि यह एलसी साख के पत्र की तारीख से काफी पहले का था। इस प्रकार पाटित वस्तुओं के संबंध में वार्ताओं की प्रक्रिया पूर्ण रूप से जाँच अवधि के भीतर शुरू हुई थी और इसलिए घरेलू बाजार में प्रचलित कीमतों पर इन प्रस्तावों का प्रभाव बिल्कुल संगत है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि बीजक प्रारूप के संविदा न होने के संबंध में निर्यातक का तर्क इस तथ्य से नकार दिया गया है कि जाँच अवधि के दौरान भी एक साख पत्र मौजूद था। प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यातक द्वारा उल्लिखित आयात संबंधी निर्णयों के बारे में प्राधिकारी डेनमार्क से कैटेलिस्ट के आयातों के मामले में निर्णय का संदर्भ देना उचित मानते हैं जो कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया था और यह एक पाटनरोधी जाँच मामले का निर्णय होने के कारण प्रत्यक्षतः प्रासंगिक है।

प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रकटन के उत्तर में यद्यपि घरेलू उद्योग ने पुनः अपने अनुरोधों को दोहराया है, परन्तु निर्यातक ने यह उल्लेख किया है कि पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए क्षेत्राधिकार एवं पाटनरोधी शुल्क लगाने का क्षेत्राधिकार मौजूद नहीं है क्योंकि परस्पर संबद्ध भ्रम है क्योंकि पाटन मार्जिन के निर्धारण के बिना किसी भी पाटनरोधी शुल्क का संग्रहण संभव नहीं है। वस्तुतः सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क में भी इस बारे में सुस्पष्टतया इंगित है। प्राधिकारी उपरोक्त अनुरोधों को नोट करने के बाद मानते हैं कि कैटेलिस्ट के मामले में जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया है में प्राधिकारी ने निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए निविदा कीमतों का संदर्भ दिया था। निर्धारण में ये स्पष्टतया इंगित किया गया था कि प्राधिकारी ने यह देखा है कि ज्यादातर कैटेलिस्ट्स निविदाओं के जरिए ही बेचे गए हैं। कीमत संविदा तथा सुपुर्दगी की वास्तविक तारीख के बीच काफी समय का अंतर है। नियमों में उल्लिखित है कि तुलना 'बिक्री' के बारे में की जानी चाहिए न कि आयातों के संबंध में। नियमों में आगे यह भी उल्लिखित है कि कीमत तुलनीयता को प्रभावित करने वाली भिन्नताओं के लिए, प्रत्येक मामले में गुणों के आधार पर देय भत्ता दिया जाए। प्राधिकारी पाते हैं कि कीमत संविदा के कारण ही कीमत कटौती या कम कीमत पर बिक्री होती है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति होती है, यह तथ्य कि सुपुर्दगी जाँच अवधि से बाहर की जा सकती है, प्रत्यक्ष महत्व का नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए, जाँच अवधि के दौरान सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत संविदा के बीच की गई तुलना वास्तविक आयात/सुपुर्दगी का संदर्भ दिए बिना की गई है।

प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि पूर्व के निर्धारण में ईयू, सिंगापुर, थाइलैंड, जापान, ब्राजील तथा कोरिया आरपी से पीआईबी और आस्ट्रिया चैक गणराज्य, रूस एवं यूक्रेन से सीमलैस ट्यूब्स के पूर्व के निर्धारणों में प्राधिकारी ने निविदा कीमतों का संदर्भ लिया है जो कि निविदा (उद्धरित) कीमतें थीं न कि जाँच अवधि के दौरान किए गए वास्तविक निर्यातों की निर्यात कीमतें। इसके अलावा, प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि निर्यातक की जाँच के दौरान, एक साख पत्र अभिज्ञात किया गया था जो भारत में वस्तु की आपूर्ति के लिए एक भारतीय क्रेता के साथ खोला गया था। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि उप-नियम (6) में पाटनरोधी नियमों के अनुबंध-1 के अनुसार, प्राधिकारी को निर्यात कीमत तथा सामान्य मूल्य के बीच उचित तलुना के द्वारा पाटन मार्जिन निर्धारित करना होता है। इसलिए प्राधिकारी मानते हैं कि इसमें बीजक प्रारूप या साख के पत्र, भारत को बिक्री के सौदों के संबंध में जो उपलब्ध हो, के द्वारा निर्यात कीमत भली प्रकार से निर्धारित है। अतः प्राधिकारी ने उपरोक्त यथा इंगित पाटन मार्जिन का निर्धारण उचित ढंग से किया है।

तुलना से संबंधित नियम निम्नानुसार हैं :-

पाटन मार्जिन निकालते समय निर्दिष्ट प्राधिकारी निर्यात कीमत और सामान्य मूल्य के बीच एक उचित तलुना करेगा। यह तुलना व्यापार के एक समान स्तर पर सामान्यता कारखाना द्वार स्तर पर की जाएगी और यथासंभव उसी समयावधि के दौरान की गई बिक्रियों के संबंध में की जाएगी। जो अंतर कीमत तुलनीयता पर प्रभाव डालते हैं उनके लिए प्रत्येक मामले में गुण दोष के आधार पर उचित छूट दी जाएगी। उक्त अंतर में बिक्री की शर्तें कराधान, व्यापार के स्तर, मात्राएं, भौतिक विशेषताएं तथा अन्य ऐसे अंतर शामिल हैं जो कीमत तुलनीयता को प्रभावित करने के लिए प्रदर्शित किए जाते हैं।

प्राधिकारी ने संबद्ध देश के सभी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए पाटन मार्जिन के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ जाँच अवधि में भारित औसत सामान्य मूल्य की तुलना निर्यात के लिए संविदाकृत वस्तुओं के लिए अधिमानित औसत कारखाना द्वार पर निर्यात कीमत के साथ की है।

निर्यातकों/उत्पादकों के लिए पाटन मार्जिन निम्नानुसार बनता है।

निर्यातक	सामान्य मूल्य (एनवी) डालर/मी0टन	निर्यात कीमत (ईपी) डालर/मीटन	ईपी के % रूप में पाटन मार्जिन
कतर			
मै0 कतर बिनाइल कम्पनी (क्यूवीसी) लि.	*****	*****	42
कतर में अन्य निर्यातक/ उत्पादक	*****	*****	47

4. क्षति एवं कारणात्मक संबंध

उपरोक्त नियम-11, अनुबंध-11 के तहत जब क्षति के बारे में किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है तो इस प्रकार के निष्कर्ष में "..... पाटित आयातों की मात्रा, घरेलू बाजार में समान वस्तुओं की कीमतों पर उनके प्रभाव तथा इस प्रकार की वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे

आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए घरेलू उद्योग को हुई क्षति का निर्धारण शामिल होगा। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय यह जांच करना आवश्यक समझा जाता है कि पाटित आयातों के कारण भारत में समान वस्तुओं की कीमत की तुलना में कीमत में कोई उल्लेखनीय गिरावट आई है अथवा नहीं अथवा क्या इस प्रकार के आयातों से कीमतों में अन्यथा उल्लेखनीय स्तर तक गिरावट आई है, कीमत वृद्धि में अन्यथा रुकावट आई है जो कि अन्यथा उल्लेखनीय स्तर तक बढ़ गई होती।

भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए हम उक्त नियमावली के अनुबंध-II (iv) के अनुसार ऐसे संकेतकों पर विचार कर सकते हैं जो उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालते हैं जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, स्टॉक लाभ प्रदत्ता, निवल बिक्री प्राप्ति, डम्पिंग की मात्रा तथा मार्जिन आदि।

जहां तक क्षति के खतरे का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमों में निम्नानुसार कहा गया है:-

"वास्तविक क्षति के खतरे का निर्धारण तथ्यों के आधार पर किया जाएगा और उनकी केवल आरोप, कल्पना अथवा परोक्ष संभावना के आधार पर। परिस्थितियों में होने वाले परिवर्तन के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली ऐसी किसी स्थिति का स्पष्ट तौर पर अनुमान लगाया जाना चाहिए और ऐसी स्थिति आसन्नवर्ती होनी चाहिए जिसमें पाटन से क्षति पहुंचेगी। वास्तविक क्षति के खतरे की मौजूदगी के संबंध में आकलन करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कारकों पर विचार करेगा:-

(क) भारत में पाटित आयातों की अत्यधिक वृद्धि पर जो पर्याप्त रूप से बढ़े हुए आयातों की संभावना को दर्शाती है।

(ख) अतिरिक्त निर्यातों को समाहित करने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए निर्यातक की क्षमता में पर्याप्त मुक्त निपटानयोग्य अथवा कोई आसन्न, पर्याप्त वृद्धि होना जिससे भारतीय बाजार को पर्याप्त रूप से बढ़े हुए पाटित आयातों की संभावना का संकेत मिलता हो।

(ग) क्या आयात ऐसी कीमतों पर होने जा रहा है जिनका घरेलू कीमतों पर दमनकारी अथवा दमनात्मक प्रभाव होगा तथा जिनसे अतिरिक्त आयातों की मांग बढ़ने की संभावना उत्पन्न होगी, और

(घ) जांच की जा रही वस्तु की सूचियाँ।

प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए क्षति आंकड़े की पुनः जांच भी की है तथा घरेलू उत्पादकों जिन्होंने आरंभ में याचिका का समर्थन किया था तथा अन्य घरेलू उत्पादकों जिन्होंने जांच आरंभ के पश्चात पर्याप्त समर्थन किया था के मामले में निम्नलिखित आर्थिक मापदंडों को पालन किया है:-

	1998-99	1999-2000	2000-2001	पीओआई (1.1.2001 से 30.9.2001)	वार्षिकृत पीओआई
क्षमता	723564	729100	729100	546825	729100
उत्पादन	528367	669488	675681	492653	656871
क्षमता उपयोग	73.02	91.82	92.67	90.09	90.09
बिक्रियां (एमटी)	450729	530357	536339	382758	510344
निवल बिक्री प्राप्ति	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
उत्पादन लागत (रु./एमटी)	****	****	****	****	****
लाभप्रदता (रु./एमटी)	****	****	****	****	****
कुल आयात	94452	86743	73621	29022	38696
कतर से आयात	0	0	0	3202	4269
कतर से आयातों का बाजार हिस्सा	0	0	0	11.03	11.04
मांग (एमटी)	1509061	1461626	1496113	1111110.345	1481480
मांग में बाजार हिस्सा					
मांग के % रूप में आयात	6.26	5.93	4.92	2.61	2.61
मांग के % रूप में भागीदार कम्पनियों का हिस्सा	29.87	36.29	35.85	34.45	34.45
मांग के % रूप में कतर से आयात	0.00	0.00	0.00	0.29	0.29

(क) घरेलू बिक्रियां 1998-99 के 450729 एमटी से बढ़कर 1999-2000 में 530357 एमटी तथा 2000-2001 में 536339 हो गई है। जांच अवधि में, वार्षिक घरेलू बिक्रियां 510344 एमटी रही हैं।

(ख) क्षमता उपयोग 1998-99 के 73.02% से बढ़कर 1999-2000 में 91.82% तथा 2000-2001 में 92.67% हो गया है। जांच अवधि में, क्षमता उपयोग 90.09% रहा है।

(ग) उत्पादन 1998-99 के 528367 एमटी से बढ़कर 1999-2000 में 669488 एमटी तथा 2000-2001 में 675681 एमटी हो गया है। जांच अवधि में, वार्षिक उत्पादन 656871 एमटी का रहा है।

(घ) 1998-99 में निवल बिक्री प्राप्ति XXXX-रूपए/एमटी रही है जो 1999-2000 में बढ़कर XXXX-रूपए/एमटी तथा 2000-2001 में XXXX-रूपए/एमटी हो गया है। जांच अवधि के दौरान निवल बिक्री प्राप्ति XXXX रूपए/एमटी रही।

(ङ) जांच अवधि में निवल बिक्री प्राप्ति गैर-क्षतिकारक कीमत से कम रही है जिसके कारण वित्तीय घाटे हुए।

(च) संबद्ध वस्तुओं का आयात 1998-99 के 94452 एमटी से घटकर 1999-2000 में 86743 एमटी तथा 2000-2001 में 73621 एमटी हो गया है। संबद्ध वस्तुओं का आयात जांच अवधि (वार्षिकृत 38696 एमटी) में घटकर 29022 एमटी हो गया है।

(छ) 2000-2001 तक कतर से आयात नगण्य थे। जांच अवधि में निर्यातक द्वारा 3202 एमटी का निर्यात बताया गया था जो जांच अवधि में संबद्ध वस्तुओं के कुल आयातों का 11.04% होता है। कतर से ये आयात जिन्हें प्रोफोर्मा बीजक द्वारा इंगित किया गया था, हाल की अवधि की तुलना में महत्वपूर्ण है और 3% के निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक हैं।

(ज) प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि कतर में निर्यातक ने निर्यात के प्रयोजनार्थ प्राथमिक तौर पर एक संयंत्र स्थापित किया है क्योंकि कतर के गृह-बाजार में विशिष्ट मांग नहीं है। इसलिए वर्तमान उपलब्ध क्षमता तथा हाल के पाटित आयातों के द्वारा कीमत कटौती के कारण, प्राधिकारी पाते हैं कि कतर से निर्यात भारत में संबद्ध वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों के लिए एक सन्निकट खतरा है।

(झ) प्राधिकारी नोट करते हैं कि कतर से निर्यातक मै0 कतर विनाइल कम्पनी की क्षमता **** डालर/एमटी के आर्डर की है जिसकी जांच मौके पर जांच के दौरान की गई थी। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह क्षमता इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण है कि कतर में कोई मांग नहीं है और निर्यातक प्राथमिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में है और भारत समेत विभिन्न देशों को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात कर रहा है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियामवली के अनुबंध-II के अनुसार वास्तविक क्षति की आशंका वाले मापदंडों में से एक यह है कि क्या भारत में पाटित आयातों की कोई महत्वपूर्ण वृद्धि दर है जो महत्वपूर्ण बढ़े हुए आयात कार्य (इम्पोर्टेशन) की संभावना को इंगित करता हो। इस संदर्भ में प्राधिकारी नोट करते हैं कि मौके पर की गई जांच के दौरान, निर्यातक मै0 क्यूवीसी ने इंगित किया था कि निर्यात हेतु उसकी लंबी अवधि वाले ठेका भारत को छोड़कर अन्य देशों के लिए है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि 3 से 5 वर्षों के दौरान मै0 क्यूवीसी द्वारा लिए गए ठेके पूरी क्षमता हेतु नहीं हैं और यह कि ऐसी लंबी अवधि वाली ठेके पर विचार करने के पश्चात भी, बिक्री हेतु अतिरिक्त क्षमता है जो कि निर्यातक के पास अन्य गैर-संविदाकृत देशों को बिक्री हेतु उपलब्ध है। इस संदर्भ में प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण की अनुक्रिया में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों को भी नोट किया है कि डीजीसीआई एंड एस के अनुसार अक्टूबर, 2001 से मार्च, 2002 के बीच संबद्ध वस्तुओं के 17000 एमटी के आर्डर का कतर से भारत को निर्यात हुआ है। यह भी इंगित किया गया है कि अन्य माध्यमिक स्रोतों से 2002 में करीब 30,000 एमटी सामग्री का निर्यात निर्यातक द्वारा किया गया है और कीमतें काफी कम रही हैं। प्राधिकारी इसलिए नोट करते हैं कि जांच अवधि के दौरान सिर्फ 3202 एमटी का ठेका हुआ था, जांच अवधि के पश्चात अक्टूबर, 2001 से मार्च, 2002 तक 13633 एमटी आर्डर का हुआ है जो महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाता है। प्राधिकारी इसलिए पाते हैं कि मै0 क्यूवीसी के पास अगले तीन वर्षों हेतु संबद्ध वस्तुओं की पर्याप्त गैर-संविदाकृत मात्रा होने से तथा जांच अवधि के पश्चात पाटित वस्तुओं की वृद्धि दर अत्यधिक होने से यह संकेत मिल रहा है कि आयात की निकट भविष्य में

पर्याप्त रूप से बढ़ने की संभावना हैं तथा जांच-अवधि के पश्चात के आयातों को ध्यान में रखते हुए वास्तविक रूप से भी बढ़ गई है। औसत कीमतें भी जिन पर जांच अवधि के पश्चात की अवधि के दौरान आयात हुए हैं सूचित करती है कि ऐसे आयात महत्वपूर्ण रूप से घरेलू कीमतों का दमन तथा ह्रास कर रहे हैं। प्राधिकारी इसलिए यह मानते हैं कि पाटित वस्तुओं से घरेलू उद्योग के लिए वास्तविक क्षति की आशंका है।

5. भारतीय उद्योग के हित तथा अन्य मुद्दे

प्राधिकारी नोट करते हैं कि मै0 नालकों ने सूचित किया है कि उनकी जरूरत काफी विशाल मात्रा की है तथा घरेलू उद्योग द्वारा किया गया ट्रक आपूर्तियां अपर्याप्त है। इसने यह भी इंगित किया है कि भारतीय आपूर्तिकर्ताओं के मामले में मै0 नालकों को पहुँच लागत काफी अत्यधिक है। मै0 नालकों द्वारा यह इंगित किया गया है कि पाटनरोधी शुल्क के कारण उनकी निर्यात कीमतें तथा प्रतिस्पर्धात्मकता अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम होंगी। उपरोक्त अनुरोध को नोट करने के पश्चात प्राधिकारी मानते हैं कि क्षति के प्रयोजनार्थ तुलना कारखाना द्वार स्तर पर की जा रही है जोकि जिसमें भाड़े का घटक शामिल नहीं है। पाटन के पहलू का मूल्यांकन भी कारखाना द्वार स्तर पर किया जाना है। जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग हेतु गैर-क्षतिकारक कीमत (एन0आइ0पी0) का विचार इस निर्धारण के पैरा-6 में यथापरिभाषित पहुँच मूल्य के साथ किया जाता है। इस प्रार सिर्फ कारखाना द्वार स्तर ही है जिस पर संगत अभ्यास के अनुसार क्षति की सीमा निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने विचार किया।

प्राधिकारी यह भी मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्कों का उद्देश्य सामान्यतया, पाटन के अनुचित व्यापार कार्यों द्वारा घरेलू उद्योग को पहुँचाई गई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में निर्बाध तथा उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति को पुनः स्थापित किया जा सके जोकि देश के सामान्य हित में है।

प्राधिकारी यह भी मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से संबद्ध वस्तुओं का प्रयोग करके विनिर्मित उत्पादों का कीमत स्तर प्रभावित हो सकता है तब और परिणामस्वरूप जैसाकि मै0 नालको द्वारा प्रस्तुत किया गया, निर्यात बाजार में इन उत्पादों की सापेक्ष प्रतिस्पर्धात्मकता पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है, तथापि, भारतीय बाजार में इन पाटनरोधी उपायों द्वारा उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी। प्रत्युत, पाटनरोधी उपायों के आरोपण से पाटन कार्यों द्वारा उठाए गए अनुचित लाभ समाप्त होंगे तथा घरेलू उद्योग का पतन रुकेगा एवं उपभोक्ताओं हेतु संबद्ध वस्तुओं का विविध पसंद की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी। पाटनरोधी उपायों को लागू करने से संबद्ध देश से आयात भी किसी भी रूप में प्रतिबंधित नहीं होंगी, और इसलिए उपभोक्ताओं हेतु उत्पादों की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि आयात-निर्यात नीति के तहत विशिष्ट स्कीम उपलब्ध है जिसके तहत मै0 नालको निर्यात उत्पादन हेतु आयात कर सकता है।

6. पहुँच मूल्य

इस उद्देश्य के लिए आयातों का पहुँच मूल्य सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के तहत सीमाशुल्क द्वारा यथा आकलित निर्धारणीय मूल्य होगा और इसमें सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3, 3क, 8ख, 9, 9क के तहत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर सीमाशुल्क के लागू स्तर शामिल होंगे।

घ. निष्कर्ष**उपरोक्त पर विचार करने के पश्चात यह देखा गया है कि**

(क) संबद्ध देश के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु का सभी रूपों में इसकी सामान्य मूल्य से कम कीमत पर भारत को निर्यात किया गया है।

(ख) निर्यातक के पास निर्यात के उद्देश्य से पर्याप्त क्षमता उपलब्ध है क्योंकि कतर में घरेलू खपत संबंधी मांग काफी कम है और हाल ही के पाटित आयातों से कीमत में ह्रास हुआ है और हाल में बढ़े हुए आयातों को ध्यान में रखते हुए भारत में संबद्ध वस्तु के घरेलू उत्पादकों को निकट भविष्य में खतरा है।

(ग) घरेलू उद्योग को पाटित संबद्ध वस्तु की कम पहुँच कीमतों की वजह से कीमत में हुए ह्रास के कारण कम निवल बिक्री प्राप्ति (एन०एस०आर०) के कारण वित्तीय हानियों के रूप में वास्तविक क्षति भी हुई है।

(घ) घरेलू उद्योग को क्षति संबद्ध देश के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन द्वारा हुई है।

(ङ.) प्राधिकारी अध्याय-28 के अंतर्गत आने वाली संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करते हैं।

(च) पाटन मार्जिन के बराबर पाटनरोधी शुल्क की राशि की सिफारिश करने पर विचार किया गया था ताकि पाटन के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त किया जा सके। तदनुसार, यह प्रस्ताव किया जाता है कि केन्द्र सरकार द्वारा सीमाशुल्क टैरिफ के अध्याय 28 सीमाशुल्क उप-शीर्ष 2815.11 एवं 2815.12 के अंतर्गत कतर मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के सभी आयातों पर निम्नांकित तालिका के कालम-3 में यथा इंगित राशि और पहुँच मूल्य के बीच अन्तर के बराबर डालर/मी०टन में पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का प्रस्ताव किया जाता है।

1	2	3
क्र.सं.	निर्यातक/उत्पादक का नाम	मूल्य (यूएस डालर/मी०टन)
1.	कतर मै० कतर विनिल कंपनी (क्यूवीसी) लि० कतर में सभी अन्य निर्यातक/उत्पादक	267.82 271.10

(छ) उपर्युक्त के अध्यक्षीन, प्राधिकारी दिनांक 18.1.2002 के प्रारंभिक जांच परिणामों की पुष्टि करते हैं।

(ज) इस आदेश के विरुद्ध कोई अपील उपर्युक्त अधिनियम के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद, स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय अधिकरण के समक्ष दायर की जाएगी।

एल.बी. सप्तऋषि, निर्दिष्ट प्राधिकारी एवं अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th October, 2002

FINAL FINDINGS**Subject : Anti-Dumping Investigation concerning imports of Caustic Soda from Qatar.**

No. 55/1/2001-DGAD.—Having regard to the Customs Tariff Act 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, thereof

A. PROCEDURE

- 1 The procedure described below has been followed with regard to the investigation
 - i) The Designated Authority (hereinafter also referred to as Authority), under the above Rules, received a written application from M/s Alkali Manufacturers Association of India (AMAI) (hereinafter referred to as petitioner) on behalf of M/s Grasim Industries, M/s Gujarat Alkalies and Chemicals Ltd, M/s Search Chem Industries Ltd, M/s DCW and M/s Indian Rayon and Industries Ltd who represented the domestic industry, alleging dumping of Sodium Hydroxide commonly known as Caustic Soda (hereinafter also referred to as subject goods) originating in or exported from Qatar (hereinafter referred to as subject country) The petition was supported by M/s Siel Chemicals Complex, Patiala, Punjab, M/s Bihar Caustic & Chemicals Ltd Bihar, M/s Jayshree Chemicals Ltd, Orissa and M/s Andhra Sugars Ltd, Saggonda unit subsequent to initiation
 - ii) Preliminary scrutiny of the application filed by the petitioner revealed certain deficiencies, which were subsequently rectified by the petitioner The petition was, therefore, considered as properly documented
 - iii) The Authority on the basis of sufficient evidence submitted by the petitioner decided to initiate the investigation against imports of subject goods from Qatar The authority notified the Embassy of Qatar in New Delhi about the receipt of dumping allegation before proceeding to initiate the investigation in accordance with sub-Rule 5(5) of the Rules

- iv) The Authority issued a public notice dated 8.10.2001 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating Anti-Dumping investigations concerning imports of the subject goods classified under custom Code 281511 and 281512 of Schedule I of the Customs Tariff Act, 1975 originating in or exported from Qatar.
- v) The Authority notified preliminary findings dated 18.1.2002 and forwarded a copy of the preliminary findings to the following interested parties, who were requested to furnish their views, if any, on the preliminary findings within forty days of the date of the letter:-

IMPORTERS/USER

1. M/s Abhey Chemicals Ltd., Baroda
2. M/s Albright Wilson Chemical Ltd., Mumbai
3. M/s Arvind Mills Ltd., Ahmedabad
4. M/s Birla Cellulose Ltd., Bharuch
5. M/s Central Pulp Mills Ltd., Delhi
6. M/s Deepak Nitrite Ltd., Nandesari
7. M/s Godrej Soaps Ltd., Mumbai
8. M/s Gujarat Electricity Board, Vadodara
9. M/s Gujara Narmada Fertilizers Co. Ltd., Bharuch
10. M/s Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd., Vadodara
11. M/s Hindustan Lever Ltd., Mumbai
12. M/s ICI India Ltd., Valsad
13. M/s Indian Farmer Fertilizers Coop. Ltd., Gandhinagar
14. M/s Indian Oil Corporation Ltd., Vadodara
15. M/s Indian Petrochemicals Corporation Ltd., Vadodara
16. M/s Jaysynth Dychem Ltd., Mumbai
17. M/s Link Pharma Ltd., Baroda
18. M/s Meghmani Organics Ltd., Ahmedabad
19. M/s Narmada Chematur Petrochemicals Ltd., Bharuch
20. M/s Nirma Ltd., Ahmedabad
21. M/s PAB Chemicals (P) Ltd., Baroda
22. M/s Rama News Prints & Papers Ltd., Surat
23. M/s Rubamin Ltd., Baroda
24. M/s Torrent Gujarat Bio-tech Ltd., Baroda
25. M/s Transpek Industries Ltd., Vadodara
26. M/s National Aluminium Ltd., Bhubaneswar, Orissa
27. M/s C.J. Shah and Company, Mumbai

EXPORTER

M/s Qatar Vinyl Company, Qatar

DOMESTIC INDUSTRY

M/s Alkali Manufacturers Association of India

- vi) The Authority also forwarded a copy of the preliminary findings to the Embassy of the subject country in New Delhi with a request that the exporters of subject goods and other interested parties may be advised to furnish their views on the preliminary findings within forty days of the date of the letter.
- vii) The Authority provided an opportunity to all interested parties to present their views orally on 29.4.2002. All parties presenting views were requested to file written submissions of the views expressed. The parties were advised to collect copies of the views expressed by the opposing parties and offer rebuttals, if any.
- (viii) Submissions in response to the preliminary findings/public hearing were made by the following interested parties:-
 - (i) M/s Alkali Manufacturers Association of India
 - (ii) M/s NALCO
 - (iii) M/s Economic Laws Practice, Mumbai on behalf of M/s Qatar Vinyl Company Ltd.
- ix) The Authority kept available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file maintained by the Authority and kept open for inspection by the interested parties as per Rule 6(7).
- (x) Request was made to the Central Board of Excise and Customs (CBEC) to arrange details of imports of subject goods made in India during the past three years, including the period of investigation. Kandla Port Trust was also requested for details of shipment. Information on imports was received from Kandla Customs and Kandla Port Authorities.
- (xi) Arguments raised by the interested parties before announcing the preliminary findings, which have been brought out in the preliminary findings notified have not been repeated herein for sake of brevity. However, the arguments raised by the interested parties subsequently have been appropriately dealt in the preliminary findings and/or these findings;
- (xii) In accordance with Rule 16 of the Rules supra, the essential facts/basis considered for these findings were disclosed to known interested parties on 20.9.2002 and comments received on the same have also been duly considered in these findings.
- (xiii) Cost investigation was also conducted to work out optimum cost of production and cost to make and sell the subject goods in India on the basis of Generally Accepted

Accounting Principles (GAAP) and the information furnished by the petitioner. The cost data of the following domestic producers was provided and analysed:--

1. M/s DCW
2. Gujarat Alkalies and Chemicals Ltd., Vadodara
3. Search Chem Industries Ltd , Jagadhia
4. Indian Rayon & Industries Ltd., Veraval, Gujarat
5. M/s Grasim Industries
6. Siel Chemicals Complex, Patiala, Punjab
7. M/s Bihar Caustic & Chemicals Ltd., Bihar
8. M/s Jayshree Chemicals Ltd, Orissa
9. M/s Andhra Sugars Ltd., Saggonda

- (xiv) The Authority verified the information provided by the petitioners to the extent considered necessary and also conducted on spot verification of the data furnished by M/s Qatar Vinyl Company, Qatar on 10th and 11th September, 2002.
- (xv) ****in this notification represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- (xvi) Investigation was carried out for the period starting from 1st January, 2001 to 30th Sept , 2001 i.e. the period of investigation (POI).

B. VIEWS OF EXPORTERS, IMPORTERS AND OTHER INTERESTED PARTIES

1. VIEWS OF M/S ALKALI MANUFACTURERS ASSOCIATION OF INDIA (AMAI)

a). STANDING OF THE PETITIONER, PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

- (i) The petitioner have reiterated their submissions on product under consideration and like article as also indicated in the preliminary findings.

In response to the disclosure, the following submissions have been made:-

The domestic industry have reiterated their submissions made earlier and have mentioned that as there are no submissions to the contrary neither any objection on the issue of product under consideration, like article and standing of the Domestic Industry, they have requested to confirm the preliminary findings.

b) NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING**DUMPING**

While the exporter from Qatar has responded, the importers have not responded which establishes our claim that importers/traders were well aware that the price at which material has been imported is a dumped price. This is a fit case for imposition of anti dumping duty on retrospective basis.

- (ii) The exporter has not filed the non-confidential summary of the questionnaire response.
- (iii) The argument of exporter regarding no imports of caustic soda in India during POI is misplaced since the relevant fact is that of fact of exports and not imports.
- (iv) The product can be considered as having been exported in various conditions like a firm offer/order of purchase, invoices and offer of resale etc.
- (v) In the instant case, during the POI an offer of supply was made by the exporter to the Indian trader.
- (vi) With regard to the normal value of exporter, the cost of production of the exporter needs to be scrutinised in detail.
- (vii) The petitioner strongly submits that under no circumstances the cost of production for the exporter can be lower since they have made a huge investment of 678 million USD. The company has not provided the actual cost of production. The company has not provided the balance sheet and profit and loss account and also the project report.
- (viii) The petitioners have cited the Hon'ble Supreme Court judgement in the Catalyst case and have indicated that Rule 6(8) in view of the project report not having been provided be applied.
- (ix) The petitioner has also requested that appropriate scrutiny pertaining to allocation and apportionment of common expenses, appropriate cost of services and interest cost etc. to be evaluated carefully.
- (x) As per the EU guidelines the evidence of export price may be obtained from the individual invoice transactions or offers. Also in the US questionnaire with regard the dumping, all those sales for which the supplies have not been completed till the date of filing the response have to be included for the purpose of price determination.
- (xi) The interested parties have confused regarding the jurisdiction to determine the dumping margin and the jurisdiction to collect the anti dumping duty. These two issues are absolutely different issues.
- (xii) The argument regarding the imports is misplaced as the fact of dumping occurs upon exports and such duty is leviable in future upon imports.
- (xiii) The Designated Authority has in the past considered offers made/orders places as sufficient to invoke anti dumping action in case of PIB and Seamless Tubes.
- (xiv) The argument of NALCO regarding holding hearing prior to preliminary findings deserves to be ignored in light of the judgement of High Court of Delhi and Supreme Court in the matter of Newsprint.
- (xv) The various rules do not contemplate hearing prior to the preliminary findings

- (xvi) Even in case of Vitrified Tiles concluded recently, Ministry of Finance did not agree for any hearing to the concerned parties.
- (xvii) NALCO being an importer cannot raise the issue of dumping and dumping margin and neither NALCO is privy to the factual information nor NALCO has any actual experience and knowledge about caustic soda production and sales.

In response to the disclosure, the following submissions have been made:-

- (i) As regard dumping, the Domestic Industry has reiterated their submissions regarding the various forms of offers/documents pertaining to exports which could be introduced into the country and have further reiterated the fact that the shipments made during the investigation period is of little relevance.
- (ii) The petitioners have also mentioned that since the Normal Value has now been determined by the Designated Authority after taking into account various submissions made by the petitioners and reassessment of the cost of production, the proposed determination should be confirmed.

c) INJURY, CAUSAL LINK AND OTHER ISSUES

- (i) The capacity of the exporter has been created considering various markets as the potential markets which include India as well.
- (ii) The threat of material injury to the Domestic Industry from Qatar is required to be seen in the context of the anti dumping duties already imposed from other countries.
- (iii) The capacity installed by exporter is 290000 MT far in excess of their domestic demand.
- (iv) The company also admits that it intends to focus on GCC countries, Australia, South East Asia and African markets. Indian market is lucrative to the exporter.
- (v) The Indian producers understands that the exporter has exported the material at USD 115/MT after September, 2001 also.
- (vi) The landed price on imports from Qatar is significant below the full cost of production and fair selling price of the Domestic Industry.
- (vii) There has been price undercutting and price suppression and price depression on account of the dumped imports.
- (viii) The Domestic Industry is making financial losses from the sale of caustic soda in the Indian market.
- (ix) The petitioner companies have lost sales to a number of customers on account of imports from Qatar.
- (x) In a short time of about 6 months, the exporter from Qatar has exported more than 10000 MT and that the anti dumping duties need to be levied from the retrospective effect.
- (xi) The threat is not a conjecture but real and imminent since the exports are understood to have been made at USD 115 per MT. The anti dumping duties should be levied in the variable dollar form.

- (xii) In response to the submissions made by NALCO, the Domestic Industry has indicated that the NALCO's demand is 100000 MT and that the Domestic Industry has catered to the requirement of NALCO in the past.
- (xiii) As regards NALCO's argument on injury, it is mentioned that the claim of Domestic Industry is not based on material injury but is based on threat of material injury.
- (xiv) The various parameters such as production, sales volume, capacity utilisation have shown decline in the investigation period as imports have started arriving towards the end of the investigation period.
- (xv) The Indian producers have taken up fleet of road tankers for supply of material to NALCO as a longterm policy to sustain business with NALCO. Whenever import prices have remained high, NALCO have conveniently placed order on the Domestic Industry.
- (xvi) NALCO has been conveniently trying avoid providing information on its imports and from the domestic sales for the past several years.
- (xvii) With regard the the determination of injury both actual or potential imports should be considered as also indicated in Rule 14(d)

In response to the disclosure, the following submissions have been made:-

- (i) The petitioners have reiterated that M/s QVC's entire production is meant for exports and that there is a threat of material injury since after September, 2001, the prices have come down to USD 115 PMT and that between October, 2001 and March, 2002 the exporter has exported 17000 MT of caustic soda as per DGCI&S data and as per their market intelligence about 30000 MT materials has been exported by the exporter.
- (ii) It has been mentioned that that threat of material injury under these circumstances is real and imminent.
- (iii) The petitioners have also reiterated that the rate of growth of exports from Qatar is too significant and that exporter from Qatar alone constitutes 3% of the Indian demand in a short time less than one year.
- (iv) Further the petitioners have mentioned that the threat has become imminent as per the information relating to production, sales and capacity utilization after the investigation period and upto June, 2002/
- (v) It has also been mentioned that the goods have been imported at prices as low as USD 80-115 PMT.
- (vi) The petitioners have requested for duty in the variable dollar basis on account of the low prices and drastic reduction in the export prices.

2. EXPORTER'S VIEWS

A) M/s Qatar Vinyl Company (QVC) Ltd.

a) NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING

DUMPING

- (i) No imports have been made during the POI i.e. 1.1.2001 to 30.9.2001 and that the imports were made after 18.10.2001. The exporters began production in June, 2001 and that the first transaction for imports into India were finally negotiated only around 12.10.2001. Sample copy of the invoice dated 12.10.2001 and bill of lading dated 12.10.2001 are enclosed as evidence.
- (ii) Section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 and Section 9B(b)(i) and (ii) mandates the levy upon importation of goods into India at less than their normal value.
- (iii) The entire analysis of dumping, injury, causal link and de minimis thresholds has to be made within the period of investigation and in a situation where there are no imports, no analysis can be made and levy would automatically fail.
- (iv) Under Rule 4(1)(a) of Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and For Determination of Injury) Rules, 1995, the duty of Designated Authority is to investigate into the existence, degree and effect of an alleged dumping in relation to imports of any article and when there are no imports, this duty cannot be discharged and there can thus be no levy of anti dumping duty.
- (v) Under Rule 14 of Anti Dumping Rules, Designated Authority is statutorily mandated terminate when there are no imports and hence no dumping. De-minimis criteria cannot be satisfied as per Rule 14(c) and 14(d).
- (vi) The applicants have made contradictory and misleading statement on the issue of importation indicating that exports have started and the shipment is shortly expected and therefore under Rule 5 (3) (b) where the evidence is not accurate, the initiation of the investigation is itself bad.
- (vii) In the preliminary findings, the levy has been recommended on the basis of the proforma invoice which under the Indian Contract Act cannot constitute an offer. The various judgements of the Hon'ble Courts have been cited.
- (viii) The oblique reference to some WTO provisions are not the mandated agreements and rules.
- (ix) Section 9 and Section 9A of the Customs Tariff Act and, Rule 4, Rule 5, Rule 12, Rule 17 of the Rules, all mandate an examination and findings of dumping, injury and causal link as regards imports. This examination is for imports during the period of investigation.
- (x) Section 9A(8) adopts the provisions of the Customs Act, 1962 inter alia for levy issues. Section 2(23) of the Customs Act, 1962 defines "imports" as bringing into India from a place outside India.

- (xi) Footnote 8 of the Anti Dumping Agreement provides 'date of sale' which is relevant to calculate the rate of exchange only.
- (xii) The Hon'ble Supreme Court in *Garden Silk Mills Limited & Anr. Vs. Union of India & Ors* 1999(113) ELT 358(SC) have declared that imports commences when goods enter the territorial water and is completed when goods are cleared into the Indian land mass.
- (xiii) It is submitted that just because the importers/traders have not responded to the Designated Authority, it cannot mean that they were well aware that the price at which material was imported in India was a dumped price'. On the contrary, the non-response by the importers/traders is appropriate since there were no imports during the POI.
- (xiv) It is a complete misunderstanding of the anti dumping provisions and an abuse of the anti dumping jurisprudence to make a case on any alleged threat of exports.
- (xv) Section 9A and Section 9B of the Customs Tariff Act clarify the levy of anti dumping duty on dumped articles and also clarify regarding no levy under Section 9 and Section 9A.
- (xvi) The Designated Authority is bound by the dictum of Hon'ble Supreme Court and even the event of imports is clearly settled.
- (xvii) M/s QVC wishes to take leave to file on record the balance sheet with the Designated Authority.
- (xviii) The project report is confidential document privy to the exporter and is not required in the standard questionnaire of the Designated Authority and also the project report is little if any thing at all is to do with the fixing of the normal value.
- (xix) The petitioner should be put to strict proof regarding the reference made to EU and US law.
- (xx) As regards the normal value, the applicant proceeds on constructed cost based on Indian cost of production whereas as per Rule 9(A)(c)(ii)(b) mandates consideration of costs in the country of origin.
- (xxi) 65% of the cost of production of caustic soda is on electricity which in India is 12 times more than that in Qatar.
- (xxii) The preliminary findings also proceed on constructed cost in India.
- (xxiii) The only reasons to reject cost of production furnished by QVC is (a) balance sheet not given as explained this was not possible as production begins in June, 2001 and no balance sheet was available in December/January when asked for and (b) some claimed difference in figures, which was minor and it was clarified that the figures of date should be looked at.

In response to the disclosure, the following submissions have been made:-

A. Dumping

- (i) The fact that the importers have not responded has no bearing on the dumping, which remains the function of the export price and normal value from Qatar.
- (ii) It is surprising to note that the domestic industry claims that no non-confidential summary was filed. Without a non-confidential summary on record, the Designated Authority could not have undertaken the verification visit.

- (iii) With reference to the statement that what is relevant is the fact of exports and not imports. It is categorically stated that there were neither exports nor imports to India during the Period of Investigation.
- (iv) It is vehemently denied that the product can be considered as having been exported in various conditions like “ a firm offer/order of purchase invoices and offer of resale etc.” This is completely contrary to the view taken by the Hon’ble Supreme Court. This position is all the more untenable given the fact that the exporter is the only manufacturer of the product under consideration in Qatar.
- (v) It is a undisputed fact that the Designated Authority have visited Qatar for verifying the record which clearly proves that with reference to the details of the cost of production and other pertinent information, it is a matter of record that all the required information has been filed and verified in keeping with the law.
- (vi) With reference to the EU and US provisions on supplies not yet made, the same cannot be used as the basis for imposing duties when no exports have been made at all. It might well be that as part of the overall investigation and the threat assessment, authorities may look at offers etc. as part of overall analysis. To apply that same rationale to a stand alone offer is without any basis in law and facts.
- (vii) With reference to the “confusion” on the jurisdiction to determine the dumping margin and the jurisdiction to collect anti dumping duty, the same are intimately linked as there can be no collection of any anti-dumping duties without the determination of a dumping margin. In fact, as the law is, the power to collect the anti dumping duties can only emanate from a determination of the dumping margin. Section 9A of the Customs Tariff Act is unequivocal in this regard.
- (viii) As regards the fact that the anti dumping duty is leviable for future imports, the Domestic Industry itself admits that even for imposition of anti dumping duty in future, “the fact of dumping occurs upon exports.”. Clearly there have been no exports or imports during the Period of Investigation on the facts of this case.

B. Normal Value

- (i) With regard to normal value, it is submitted that while the domestic sales are inadequate for the purposes of establishing the normal value, the export price to third countries remains an option. While the Designated Authority has the discretion to decide which basis to use (i.e. cost of production or export price to third countries) the exercise of this discretion must bring with it a transparent exercise of this discretion.
- (ii) The Designated Authority provides no reason for opting for the cost of production over the export price to third countries.
- (iii) It is submitted that there are few steps in newly establish company when it goes from project stage to industrial production. For QVC, the following were the benchmarks-

Performance Test completed	***
Lenders Reliability Test completed	***
Engineering and Project completion	***

So therefore, the commercial production is slated to be commenced only in ***. The Designated Authority should consider all this fact when considering the commercial production.

- (iv) Since QVC was able to run the plan at 72% capacity at initial stage does not mean commercial production. With reference to the capacity utilisation at 72% and the Designated Authority accepting the same as the basis for determining the cost of production, the same is highly objectionable, as no plant, especially a new plant is set up to operate at a capacity utilisation of less than ***. This is sound business practice and by ignoring this the Designated Authority is disregarding commercial realities of the economies of plant operations. At 72% capacity utilisation, making of profits on a sustained basis is highly improbable.

C. Arguments pertaining to no Exports during the Period of Investigation

- (i) The concept of “introduction into the commerce of the country” drawn upon from Article 2.1 of the WTO Agreement by the Designated Authority is without any basis. It is a matter of settled law that the Municipal law prevails over any Treaty provisions in India. The fact is that the relevant section calls for the Export of the products under consideration during period of investigation to India. Furthermore, the cases relied upon by the Designated Authority including the South Africa case may have considered tender prices as one of the constituents to determine the export price but certainly none of the cases referred to by the Designated Authority relied upon a tender price. Furthermore, within the factual matrix of the case in hand, there has been no tender during the period of investigation pursuant to which any supplies were made.

b) INJURY, CAUSAL LINK AND OTHER ISSUES

- (i) All imports in October after the POI were under advance licence and cannot cause injury during the POI.
- (ii) The Application and the preliminary findings proceed on the basis of a threat of material injury. The provisions of Rule 11(2) with para (vii) of Annexure II have been relied upon.
- (iii) The proceedings on the basis of a threat of material injury are entirely on conjecture and are entirely without jurisdiction. Even for threat of material injury, the essential requirements of satisfying the fundamental pre-conditions are essential and as such during period of investigation there are no imports.
- (iv) Harmoniously construed under Para (vii) of Annexure II there must be dumped imports in the period of investigation and while there may be no injury in the period of investigation, material injury must be threatened and imminent beyond the period of investigation. Without dumping in the period of investigation, there can be no sustainable case for a threat of material injury.

- (v) The petitioners are mutli-product company and that the petitioners are making super profits in the manufacture of Chlorine and that the Designated Authority should examine the claim of losses that petitioners have claimed

In response to the disclosure, the following submissions have been made:-

On the issue of threat of material injury

- (i) Under Section 9B(ii) read with Rule 11 and read with Para (vii) of Annexure II to the Rules are provisions which specify the threat of material injury all of which empahsize that there must be dumping (within the period of investigation) and this dumping must create an imminent threat of material injury. This is clearly brought forth from Para (viii) above which states

“The change in circumstances which would create a situation in which the dumping would cause injury must be clearly foreseen and imminent”.

- (ii) The provision for threat of material injury does not water down or obviate the essential requirements of satisfying the fundamental pre-conditions of establishing

- (i) Dumping
- (ii) Standing
- (iii) De minimis

- (iii) During the analysis period (Period of Investigation) in a situation where there are no imports during the Period of investigation, the essential pre-condition for levy are not satisfied. These essential pre-conditions cannot be given a go by in a proceeding based on a threat of material injury. In the instant case, during the verification visit made, a list of long term contract for the product under investigation were submitted which covered ****% of the total production to other third countries were made available, which clearly should be considered by the Designated Authority.
- (iv) Harmoniously constructed under Para (vii) of Annexure II there must be dumped imports in the Period of Investigation and while there may be no injury in the Period of Investigation, material injury must be threatened and imminent beyond the period of investigation. Without dumping in the period of investigation, they can be no sustainable case for a threat of material injury.
- (v) It is therefore submitted that the Designated Authority follows the judgement gives effect to the judgement delivered by the Panel report in the case of Mexico-Anti dumping investigation of High Fructose Corn Syrup (HCFS) from the United States, at Para 7.131, where before the panel USA claimed that a determination of threat of injury cannot be based only on examination of the factors set forth in Article 3.7 of the Anti Dumping Agreement. A determination of threat of injury also requires an assessment of the impact of imports on the Domestic Industry through a examination of the relevant economic factors set forth in Article 3.4. Article 3.7 requires a determination whether material injury would occur, Article 3.1 requires that a

determination of injury, including threat of injury, involve an examination of the impact of imports, and Article 3.4 sets out the factors that must be considered, among other relevant factors, in the examination of the impact of imports on the Domestic Industry. Thus, in our view, the text of the Anti Dumping Agreement requires consideration of the Articles 3.4 factors in a threat determination. Article 3.7 sets out additional factors that must be considered in a threat case, but does not eliminate the obligation to consider the impact of dumped imports on the Domestic Industry in accordance with the requirements of Article 3.4.

On the issue of injury

- (i) It is mandated in Annexure II to the Rules, that for a determination of injury “ an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry must be examined unless the circumstances are exceptional it is not possible to merely decide to determine the issue of injury on few economic negative indices while ignoring other positive indices”.
- (ii) In the case of European Commission – Anti Dumping Duties on imports of Cotton Type Bed Linen from India –Report of the Panel –WT/DS141/R at Para 6.154 that under Article 3.4, the ordinary meaning of the provision is that the examination of the impact of dumped imports must include an evaluation of all the listed factors in Article 3.4 of the WTO Agreement on Anti Dumping. In the Bed Linen case, India asserted that all relevant injury factors must be evaluated. Therefore it was the conclusion of the panel that “use of the phrase” shall include” in Article 3.4 that the evaluation of the listed factors in that provision is properly interpreted as mandatory in all cases.
- (iii) Therefore, since the above interpretation on all factors of injury to be evaluated was suggested by India and accepted by the Panel, obligates the Designated Authority to take into consideration all the injury parameters, through at the same time, it is an accepted position in the preliminary findings which cannot be ignored , that
 - (i) all indices such as sales, capital utilisation, production, net sales realisation and demand have gone up.
 - (ii) Imports have gone down
 - (iii) All injury parameters are positive
- (iv) Thus, there is clearly no injury in the Period of Investigation. It is relevant that the Domestic Industry has already had an anti dumping duty for over a year, which has obviated any material injury to Domestic Industry. The aforementioned factors establish inter alia that there is no causal link.

B. EMBASSY OF STATE OF QATAR, NEW DELHI

- (i) The Embassy of the State of Qatar has requested that the findings should be done in accordance with the principles and procedures agreed upon in the WTO.

3. IMPORTER'S VIEWS

VIEWS OF M/S NATINAL ALUMINIUM COMPANY LTD. (NALCO)

a) NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING

DUMPING

- (i) There have been no imports from M/s QVC during the POI. The billing of lading and other materials indicate exports in October, 2001. There could be no dumping when the actual imports of goods into India and that as per Section 9(A) (1) of the Customs Tariff Act, 1995 there could be no duty. Also as per Rules 4(1)(a) since there is no import, there could be no existence of dumping and therefore degree or effect of dumping cannot be investigated
- (ii) The word 'import' has been defined in the Customs Act and means the actual bringing into of goods at the customs frontiers
- (iii) Section 9(A)(1)(b) has defined the export price and it specifically means the price of the article exported from the exporting country.
- (iv) Actual import of goods is a condition precedent for imposition of anti dumping duty.
- (v) The offer or a proforma invoice is not a concluded contract and there are various judgements of courts on the same. Also proforma invoice is totally irrelevant since there could be high sea sales which could divert the goods to some other country so that it could not be termed as imports.
- (vi) Designated Authority in the case of PSF did not accept that the invoice relating to the subsequent imports took place by M/s Reliance which was within the period of investigation and the actual import was outside the period of investigation.
- (vii) There is non-disclosure of information pertaining to cost of production for both the domestic industry and the exporter and that this is denial of natural justice. While considering the cost of production for the petitioners, it should be borne in mind that the Electro Chemical Unit (ECU) realisation price is important.
- (viii) In the preliminary findings most of the information pertaining to Normal Value and adjustments have been kept confidential and that NALCO submits that it should first be provided all the material for the purpose of natural justice and defence
- (ix) While constructing the cost of production of Caustic Soda in a foreign country like Qatar, it is essential to consider the production of chlorine and the sales realisation from chlorine also as has also been admitted by the petitioner during the oral hearing that in foreign countries chlorine is the main product and caustic soda is the bye-product.
- (x) The Authority should consider the fact that the exporter is not selling at a price less than the Normal Value for the purpose of levy of anti dumping duty.

b) INJURY, CAUSAL LINK AND OTHER ISSUES

- (i) Various judgements pertaining to interpretation of international law vis-à-vis municipal law as have been indicated by NALCO for appropriate consideration.
- (ii) NALCO has also submitted that before the preliminary findings as per Section 12, a hearing for the purpose of defence should been granted and that it is the pre-decisional hearing prior to preliminary findings which is contemplated in the rules and not post-hearing decision.
- (iii) Also the rules do not exclude a prior hearing before a preliminary findings.
- (iv) The cost of production in Qatar because of the cost of electricity is much lower and that there could be no dumping.
- (v) The Rules and Acts does not admit to any conjectures and surmise but there has to be sufficient evidence to show that dumping is taking place and secondly it has caused material injury to the Domestic Industry.
- (vi) The price of caustic soda in India has been in accordance with the international price of goods and has nothing to do with the price of imported goods.
- (vii) NALCO for its supply requirement had invited tenders for supply of caustic soda lye. With present requirement of 2 lakhs MT of caustic soda lye (1 lakh MT of caustic soda dry), the Indian manufacturers have offered quantities much lower than the amounts required by NALCO making it unnecessary expensive for NALCO.
- (viii) The supplies are made by trucks carrying 10 MT only whereas normal shipment taken by NALCO in the range of 5000 MT. The supplies made by the domestic suppliers are of small quantities as compared to foreign suppliers and that the landed cost to NALCO is higher in case of Indian suppliers. This adversely affects NALCO exports and competitiveness in the Indian market.
- (ix) There are fundamental errors in the preliminary findings. The analysis holds in favour of no injury. It has been show that domestic sales, capacity utilisation, production, net sales realisation have increased and that imports have decreased and there are no imports in POI and that the demand has increased. Therefore all these factors hold that there is no injury to the Domestic Industry. The Authority has been totally arbitrary in holding that the net sales realisation in the POI has been below the NIP. It is not clear as to how the NIP has been calculated.
- (x) The net sales realisation have not taken into account the realisation from chlorine

C. EXAMINATION BY AUTHORITY

The foregoing submissions made by the exporter and the petitioner, to the extent these are relevant as per Rules and have a bearing upon the case, have been examined, considered and dealt with at appropriate places in these findings.

1. STANDING OF THE PETITIONER, PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

The Authority notes that there are no submissions made regarding the product under consideration, like article and the standing of the Domestic Industry. The Authority,

therefore, proposes to confirm the findings on these aspects as indicated in the preliminary findings dated 18.1.2002.

a) PRODUCT UNDER CONSIDERATION

The Authority recalls and reiterates Para C.1 on the product under consideration of the preliminary findings dated 18.1.2002 as under:-

The product under consideration in the present investigation is Sodium Hydroxide (chemical nomenclature NaOH), commonly known as Caustic Soda originating in or exported from Qatar. Caustic soda is an inorganic, soapy, strongly alkaline and odourless chemical and finds application in various fields like manufacture of pulp and paper, newsprint, viscose yarn, staple fibre, aluminium, cotton, textiles, toilet and laundry soaps, detergent, dyestuffs, drugs and pharmaceuticals, petroleum refining etc.

Caustic soda is classified under chapter 28 of the customs Tariff Act, 1975 under Customs Head 2815.11 and 2815.12. As per ITC Eight Digit classification, the product is classified under the Custom Heading 2815.1101, 2815.1102 and 2815.1200. The classification, is however, indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.

Caustic soda is produced in two forms, i.e. lye and solids by three technology processes, i.e mercury cell process, diaphragm process and membrane process.

Caustic Soda can be imported under OGL and attracts a basic customs duty of 35%. The present investigation covers all forms of caustic soda.

The Authority confirms the same in view of no submissions.

b) LIKE ARTICLE

The Authority recalls and reiterates Para C.2 on the Like Article of the preliminary findings dated 18.1.2002 as under:-

The Authority notes that the petitioner has claimed that the goods produced by them are like article to the goods produced, and exported from the subject country. Also both are technically and commercially substitutable and the consumers are using the domestically produced and imported goods interchangeably. It has been indicated that the Caustic soda is processed by three processes viz. Mercury cells process, diaphragm process and membrane process world over. The difference in these processes does not mean difference in product in terms of various characteristics. Also there is no significant difference in the cost of production for the three processes. The petitioner has claimed that the goods produced by them and those exported from Qatar are like article within the meaning of the Rules.

The Authority notes that the exporter from Qatar has submitted that the petitioners have made certain assumptions about the cost and the manufacturing processes. The exporter has indicated that as per their understanding there is a significant difference in the power consumption for each of the three manufacturing processes and thus the costs involved in each process. It has been submitted by the exporter that the Indian producers do not have many outlets for Chlorine and that they consider Chlorine as a non-tradable commodity and thus as a by-product while producing Caustic Soda. The exporter has indicated that in their case Chlorine is the main raw material and they do not consider it as a by-product. In fact Caustic is the by-product while producing Chlorine.

The Authority after noting the above submissions notes that while M/s QVC, the exporter from Qatar has indicated the difference in costs for the three processes, there has been no argument regarding any variation in the characteristics of the product exported by them and that produced by the Domestic Industry. It is also not a claim by the exporter that the goods exported by them and that produced by the Domestic Industry are not interchangeable. The customers in India of the goods exported by M/s QVC have used the exported goods and the goods produced by the Domestic Industry interchangeably being the common customers.

The Authority confirms the same in view of no submissions by any interested parties and holds that domestically produced goods and those exported by M/s QVC are like article as per Rule 2(d).

c) **STANDING OF THE DOMESTIC INDUSTRY**

The Authority recalls Para C.2 on the Standing of the Domestic Industry of the preliminary findings dated 18.1.2002 as under:-

The petition has been filed by M/s Alkali Manufacturers Association of India on behalf of the domestic industry. The petition has been supported by M/s DCW Limited Mumbai, M/s Gujarat Alkalies & Chemicals Ltd, Gujarat, M/s Search Chem. Industries Ltd, Mumbai, M/s Grasim Industries Ltd, Madhya Pradesh and M/s Indian Rayon & Industries Ltd., Gujarat. None of the domestic producers has opposed the petition. The Authority notes that the five domestic producers who have supported the petition constitute 32.6% of the total domestic production and therefore have the standing to file the petition on behalf of the domestic industry as per Rule 5(a) and (b) of the Anti-Dumping Rules. Subsequent to the initiation M/s Siel Chemicals Complex, Patiala, Punjab, M/s Bihar Caustic & Chemicals Ltd., Bihar, M/s Jayshree Chemicals Ltd, Orissa and M/s Andhra Sugars Ltd., Saggonda unit have also supported the petition and furnished injury information.

The Authority notes that there is no opposition to the petition by any of the domestic producers and therefore confirms the standing of the Domestic Industry in view of no submissions, and holds that the petitioner satisfies the condition as per rule 5(3) (a) and (b) and represents Domestic Industry as per Rule 2(b).

2. DUMPING MARGIN

a) NORMAL VALUE

The Authority recalls its observations on the Normal Value in the disclosure statement that it has been indicated by M/s Qatar Vinyl Company (QVC) that there are no domestic sales of the subject goods in their country. Also it has been indicated that the constructed cost of production indicated for M/s QVC by the petitioner is not correct and that there is no relevance of project report as far as exporter's response to the questionnaire is concerned. The exporter has also indicated that there is a wide variation in the cost of power in India and Qatar which is one of the major constituents for the production of Caustic Soda.

The Authority after noting the above submissions by various interested parties had carried out on spot verification of the exporter on 10th and 11th September, 2002 and has appropriately considered the concerns of the interested parties while looking at the submissions and the data provided by the exporter. The Authority in view of the various submissions made by the Domestic Industry and the exporter on the determination of the Normal Value had proposed to reference the cost of production of M/s QVC for Normal Value so verified during the on site verification of the records of the exporter conducted by the verification team on 10th and 11th September, 2002 at Doha, Qatar.

The Authority in disclosure had indicated that during the verification of M/s QVC at Doha also noticed that there was no domestic sales during the POI for the subject goods in Qatar. It was indicated by the exporter that there are certain sales of vary small quantities to their shareholding company i.e M/s QAPCO which however were not at the market price. The Authority in view of these submissions and data so verified had proposed to reference the cost of production of the subject goods during the POI for M/s QVC as ****\$/MT and with a reasonable profit margin has evaluated the Normal Value as ****\$/MT. The Authority notes that during the verification the exporter indicated that during the POI they were operating at a capacity utilisation of 72% which was a trial production stage and not commercial production. The Authority had observed in the disclosure that such a level of capacity utilisation cannot be termed as trial production and that the actual cost of production during the POI has to be considered for the determination of the Normal Value and had therefore indicated to consider the cost of production and the Normal Value on the basis of the actual production during the POI.

The Authority notes that it has been indicated by the exporter that 72% of the production during the POI was actually a trial production only and that the design of the plant was such that 72% could be termed only as trial production. It has also been indicated by the exporter that it is not clear as to why the Authority has not referenced the third country exports as the basis of the normal value. The Authority also notes that the Domestic Industry while reiterating its submissions on the Normal Value as made earlier has indicated that the Authority may confirm the findings in view of the verification so

conducted. The Authority after noting the above submissions reiterates that during the period of investigation which has been so considered, it is the actual cost of production data which is of relevance and which has therefore been considered for the purpose of evaluating the normal value. The Authority also notes that during the on spot verification of the exporter, the data pertaining to exports made to various countries during the POI was also referenced. However for the purpose of referencing the third country exports, the Authority notes that the appropriate third country in terms of quantity of exports and being in the Asian region could be Malaysia. The representative, viable and in ordinary course of trade export price to Malaysia during the POI also correlates with the Normal Value so constituted for the exporter. Also the Authority notes that even if the so called projected capacity utilisation as per project report is referenced, then reasonable profit would be the profit envisaged in the project report, the Normal Value then evaluated on the projected profit mark up on the FOB sales would also co-relate with the Normal Value so constructed by the Authority. Therefore the Authority notes that the Normal Value constructed on the basis of the actual cost of production during the POI is realistic as it correlates well with the data on the third country exports and even as indicated in the project report.

The Authority has therefore referenced the Normal Value as ****\$/MT.

b) EXPORT PRICE

The Authority recalls that in the disclosure it was indicated that the exporter has provided the CIF export price contracted during the POI and the supplies made in pursuance of this thereafter outside the POI as ****\$/MT. The exporter had provided evidence regarding various adjustments on CIF price on ocean freight, ocean insurance, marketing fee to M/s Atofina, credit cost and port expenses to an extent of ****, ****, ****, **** and **** respectively.

The ex-factory export price on the basis of the various adjustments was proposed to be considered as ****\$/MT. The Authority in view of no submission in this regard, proposes to confirm the ex-factory export price as ****\$/MT.

c) OTHER NON-COOPERATIVE EXPORTERS/PRODUCERS

As regards the other non-cooperative exporters/producers, the Authority had proposed to consider in the disclosure the Normal Value as determined for M/s QVC for these exporters/producers as well keeping in view the fact that there are no domestic sales and that the cost of production in Qatar for M/s QVC would also be relevant for the other exporters/producers.

As regards the ex-factory export price, the Authority had proposed to allow an adjustment on account of inland freight on the export price for the non-cooperative exporters/producers which led to an ex-factory export price of ****\$/MT. The Authority in view of no submissions confirms the ex-factory export price as ****\$/MT.

Based on the above, the dumping margin comes to ****\$/MT(47%).

3. **Dumping-Comparison of Normal Value & Export Price**

The Authority recalls that in disclosure statement it had indicated the views of the various interested parties pertaining to no exports by M/s QVC made during the POI. The Authority had indicated the submissions by the exporter regarding the definition of dumping, relevant provisions of the Customs Tariff Act, Hon'ble Supreme Court judgements cited, regarding the term 'imports' and contract and also the rule position pertaining to duties of the Designated Authority to evaluate the incidence of dumping. It was also indicated by the exporter that that in view of the no imports/exports during the POI, there is no incidence of dumping and that the further tests pertaining to this cannot be applied. The Authority in this regard had noted the submissions made by the Domestic Industry regarding the practices of EU and US. The Authority also noted that in case of anti dumping investigation of Catalyst from Denmark, a judgement upheld by the Hon'ble Supreme Court, Authority had categorically held that the comparison for dumping margin has to be made for sales and not for imports.

The Authority also noted the submission that it had categorically been indicated in this case that it was the price contract which leads to price undercutting and that the supply being made outside the POI was of no direct significance. The Authority noted that it has also in the past in its various determinations which included Catalyst from Denmark, PIB from EU, Singapore, Thailand, Japan, Brazil and Korea RP and Seamless Tubes from Austria, Czech Republic, Russia and Ukraine has considered the aspect of tender prices for the purpose of evaluation of export price and thereafter even for the purpose of levy of anti dumping duty. The Authority also noted that South Africa in one of the cases of Antibiotics against India had also considered the tender prices for the purposes of determination of the export price. On perusal of the Article 2.1 of the WTO Agreement on Anti Dumping, the Authority notes that the basic tenet of dumping is indicated to be introduction of the goods into the commerce of the country. In view of the fact that the contracts/tender prices when quoted lead to price undercutting and these are actually translated into shipment leading to injury even though the dumped goods may be sent outside the period of investigation. The Authority therefore notes that in case of M/s QVC, a letter of credit (LC) was opened with one of the importers during the month of September, 2001 i.e. with the POI and the correspondence which had led to a conclusion of this LC was even much prior to the date of letter of credit. The process of negotiation of the dumped goods had therefore started well within the period of investigation and therefore the impact of these offers on the prices prevailing in the domestic market is what is relevant. The Authority notes that the argument of the exporter regarding the proforma invoice not being a contract is negated by the fact that there also exists a letter of credit during the period of investigation. The Authority notes that as regards the judgements pertaining to imports being cited by the exporter, the Authority considers it appropriate to reference the judgement in case of imports of Catalyst from Denmark which was upheld by the Hon'ble Supreme Court and is of direct relevance being an anti dumping investigation case judgement.

The Authority notes that in response to the disclosure while Domestic Industry have again reiterated their submissions, the exporter has mentioned that the confusion on the jurisdiction to determine the dumping margin and the jurisdiction to levy the anti dumping duty is misplaced since the two issues are intimately linked as there can be no collection of any anti dumping duty without determination of a dumping margin. In fact the Section 9A of the Customs Tariff Act has indicated as unequivocal in this regard. The Authority after noting the above submissions holds that in case of Catalyst which has been upheld by the Hon'ble Supreme Court the Authority had referenced the tender prices for determination of the export price. It was clearly indicated in the determination that "the Authority has observed that the majority of catalysts are sold through tenders. There is a considerable time lag between the price contract and the date of actual delivery. The rules provides that comparison is required to be made in respect of the "sales" and not imports. The rules further provide that due allowance shall be made in each case, on its merits, for differences which affect price comparability. The Authority observes that it is the price contract which leads to price undercutting or underselling causing injury to the Domestic Industry, the fact that the deliveries may be made outside the investigation period is of not direct consequence". In view of the same, comparisons have been made between the Normal Value and the export prices contracted during the investigation period without reference to the period of actual import/deliveries.

The Authority also notes that in the past in the determinations of PIB from EU, Singapore, Thailand, Japan, Brazil and Korea RP and Seamless Tubes from Austria, Czech Republic, Russia and Ukraine the Authority has referenced the tender prices which were the tender (quoted) prices and not the export prices of physical exports made during the POI. Further the Authority also notes that during the verification of the exporter, a letter of credit was identified which were opened with an Indian buyer for supply of the goods to India. The Authority also notes that as per Annexure 1 of the Anti Dumping Rules in Sub-Rule (6), the Authority has to determine the margin of dumping by making a fair comparison between the export price and the Normal Value. The Authority therefore holds that in this the export price is well established by the proforma invoice or the letter of credit whichever is available in respect of the sales transactions to India. The Authority has therefore appropriately determined the dumping margin as indicated above.

The rules relating to comparison provides as follows:

"While arriving at margin of dumping, the Designated Authority shall make a fair comparison between the export price and the normal value. The comparison shall be made at the same level of trade, normally at ex-works level, and in respect of sales made at as nearly possible the same time. Due allowance shall be made in each case, on its merits, for differences which affect price comparability, including differences in conditions and terms of sale, taxation, levels of trade, quantities, physical characteristics, and any other differences which are demonstrated to affect price comparability."

The authority has carried out weighted average normal value comparison with the weighted average ex-factory export price for the goods contracted for exports in Period of

Investigation, for evaluation of the dumping margin for all the exporter/producers of the subject country.

The dumping margin for exporter/producers comes as under:

Exporter	Normal value(NV) \$/MT	Export Price(EP) \$/MT	Dumping margin as % of EP
<u>QATAR</u>			
M/s Qatar Vinyl Company (QVC) Ltd.	*****	*****	42
All other exporters/producers in Qatar	*****	*****	47

4. INJURY AND CAUSAL LINK

Under Rule 11 supra, Annexure-II, when a finding of injury is arrived at, such finding shall involve determination of the injury to the domestic industry, “.....taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles....” In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, we may consider such indices having a bearing on the state of the industry as production, capacity utilisation, sales quantum, stock, profitability, net sales realisation, the magnitude and margin of dumping, etc. in accordance with Annexure II(iv) of the rules supra.

As regards the threat of injury, the Authority notes that the Anti-Dumping Rules states as follows:

“A determination of a threat of material injury shall be based on facts and not merely on allegation, conjecture or remote possibility. The change in circumstances, which would create a situation in which the dumping would cause injury, must be clearly foreseen and

imminent. In making a determination regarding the existence of a threat of material injury, the DA shall consider, inter-alia, such factors and;

- a) a significant rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation;
- b) sufficient freely disposable or an imminent, substantial increase in capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian market, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports;
- c) whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices, and would likely increase demand for further imports; and,
- d) inventories of the article being investigated.

The Authority has also reexamined the injury data as provided by the petitioner and observes the following economic parameters in the case of domestic producers who had supported the petition initially and other domestic producers who have subsequently supported and provided injury information after initiation:-

	1998-99	1999-2000	2000-01	POI (1.1.2001 to 30.9.2001)	Annualized POI
Capacity	723564	729100	729100	546825	729100
Production	528367	669488	675681	492653	656871
Capacity utilisation	73.02	91.82	92.67	90.09	90.09
Sales (MT)	450729	530357	536339	382758	510344
Net Sales Realisation	****	****	****	****	****
Cost of production (Rs/MT)	****	****	****	****	****
Profitability (Rs/MT)	****	****	****	****	****
Total imports	94452	86743	73621	29022	38696
Imports from Qatar	0	0	0	3202	4269
Market share of imports from Qatar	0	0	0	11.03	11.04
Demand (MT)	1509061	1461626	1496113	1111110.345	1481480

Market share in demand					
Imports as % of demand	6.26	5.93	4.92	2.61	2.61
Participating companies share as % of demand	29.87	36.29	35.85	34.45	34.45
Imports from Qatar as % of demand	0.00	0.00	0.00	0.29	0.29

- a) The domestic sales has increased from 450729 MT in 1998-99 to 530357 MT in 1999-2000 and further to 536339 MT in 2000-2001. In the POI, the annualised domestic sales has been 510344 MT.
- b) The capacity utilisation has increased from 73.02% in 1998-99 to 91.82% in 1999-2000 and to 92.67% in 2000-2001. In the POI, the capacity utilisation has been 90.09%.
- c) The production has increased from 528367 MT in 1998-99 to 669488 MT in 1999-2000 and further to 675681 MT in 2000-2001. In the POI, the annualised production has been 656871 MT.
- d) The Net Sales Realisation has been **** Rs/MT in 1998-99 which has increased to **** Rs/MT in 1999-2000 and to Rs. **** Rs/ MT in 2000-2001. In the POI, the Net Sales Realisation has been to **** Rs/ MT.
- e) The Net Sales Realisation in the POI has been below the Non-Injurious Price thus leading to financial losses.
- f) The imports of the subject goods have decreased from 94452 MT in 1998-99 to 86743 MT in 1999-2000 and to 73621 MT in 2000-2001. The imports of the subject goods have further decreased to 29022 MT in POI (Annualised 38696 MT).
- g) The imports from Qatar were Nil till 2000-2001. Exports of 3202 MT were quoted by the exporter in the POI which constitute 11.04% of the total imports of the subject goods in POI. These exports from Qatar which were indicated by proforma invoice are significant as compared to earlier periods and are above the de-minimus level of 3% .
- h) The Authority also notes that the exporter in Qatar has set up a plant primarily for the purposes of export as the demand in the home market of Qatar is not significant.

by the recent dumped imports, the Authority holds that the exports from Qatar are an imminent threat to the domestic producers of the subject goods in India

- i) The Authority notes that the capacity of the exporter M/s Qatar Vinyl Company from Qatar is of an order of ****\$/MT which was verified during the on site verification. The Authority also notes that this capacity is significant in view of the fact that there is no available demand in Qatar and that the exporter is primarily into international business and is exporting the subject goods to various countries including India. The Authority notes that as per Annexure II of the Anti Dumping rules one of the parameters pertaining to threat of material injury is to examine as to whether there is a significant rate of increase of dumped imports into India which indicate the likelihood of substantial increased importation. The Authority in this regard notes that during the on site verification, exporter M/s QVC had indicated that their long-term contract for supply to countries other than India. The Authority notes that the contracts which have been committed over a period of 3 to 5 years by M/s QVC are not for the entire capacity and that even after consideration of such long-term contracts, there is surplus disposable capacity which is available with the exporter for sales to other non-contracted countries. The Authority in this regard has also noted the submissions made by the Domestic Industry in response to the disclosure that as per DGCIS between October, 2001 and March, 2002 there have been exports of an order of 17000 MT of subject goods to India from Qatar. Also it has been indicated that from the other secondary sources in 2002 about 30000 MT material has been exported by the exporter and that the prices have been significantly lower. The Authority therefore notes that while only 3202 MT which were contracted during the POI, the exports subsequent to the POI from October, 2001 to March, 2002 have been to an order of 13633 MT which represents a significant increase. The Authority therefore holds that there being sufficient non-contracted quantity of subject goods for the next three years with M/s QVC and that there has been significant rate of increase of dumped goods beyond the POI thereby implying that the likelihood of substantial increased importation is imminent and to a great extent has also become real in view of the substantial post-POI imports. Also the average prices at which the imports have taken place during the post-POI period imply that these imports are significantly depressing and suppressing the domestic prices. Thus the authority holds that the dumped goods are a threat of material injury to the Domestic Industry.

5. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES

The Authority notes that M/s NALCO have indicated that their requirement is of much higher quantities and that the truck supplies made by the Domestic Industry are insufficient. It has also indicated that the landed cost to M/s NALCO is much higher in case of the Indian suppliers. It has also been further indicated by M/s NALCO that on account of the anti dumping duty, their export pricing and competitiveness would get affected in the international market. The Authority after noting the above submissions holds that the comparison for the purpose of injury is being done at the ex-factory level which does not include the element of freight. The aspect of dumping is also to be evaluated at the ex-

factory level. The Non-Injurious Price (NIP) considered for the Domestic Industry during the POI is done with the landed value as defined in Para 6 of this determination. Thus it is only the ex-factory level which the Authority considered for the purpose of determining the extent of injury as per its consistent practice.

The Authority also holds that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country.

The Authority also recognises that though the imposition of anti-dumping duties might affect the price levels of the products manufactured using the subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of these products in export market as submitted by M/s NALCO, however, fair competition in the Indian market will not be reduced by these anti-dumping measures. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantages gained by the dumping practices and would prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice of the subject goods to the consumers. Imposition of anti-dumping measures would also not restrict imports from the subject country in any way, and, therefore, would not affect the availability of the products to the consumers. The Authority also notes that there are specific schemes available under the Export-Import policy under which M/s NALCO could import for the purpose of export production.

6. LANDED VALUE

The landed value of imports for the purpose shall be the assessable value as determined by the customs under Customs Tariff Act, 1962 and applicable level of custom duties except duties levied under Section 3, 3A, 8B, 9, 9A of the Customs Tariff Act, 1975.

D. CONCLUSIONS:

It is seen, after considering the foregoing, that:

- a) The subject goods in all forms originating in or exported from the subject country have been exported to India below its normal value.
- b) The significant disposable capacity for export purposes available with the exporter since there is very low home consumption demand in Qatar and the recent dumped imports have caused price depression and is an imminent threat to the domestic producers of the subject goods in India in view of recent increased imports.
- c) The domestic industry has also suffered material injury by way of financial losses due to depressed Net Sales Realisation (NSR) on account of price depression caused by low landed prices of the dumped subject goods.
- d) The injury has been caused to the domestic industry by dumping of the subject goods originating in or exported from the subject country.

- e) The Authority recommends anti-dumping duty on imports of subject goods falling under Chapter 28 originating in or exported from the subject country
- f) It was considered to recommend the amount of anti-dumping duty equal to the margin of dumping so as to remove the injury to the domestic industry accrued on account of dumping. Accordingly, it is proposed that anti dumping duty equal to the difference between the amount as indicated in Column 3 of the Table below and the landed value in \$/MT be imposed, by the Central Government, on all imports of subject goods originating in or exported from Qatar under Chapter 28 Customs sub-heading, 2815 11 and 2815 12 of the Customs Tariff

1	2	3
Sl. No.	Name of the exporter/producer	Amount (US\$/MT)
1.	<u>Qatar</u>	
	M/s Qatar Vinyl Company(QVC) Ltd.	267.82
.	All other exporters/producers in Qatar	271.10

- g) Subject to above, the Authority confirms the preliminary findings dated 18.1.2002
- h) An appeal against this order shall lie to the Customs, Excise, Gold (Control) Appellate Tribunal in accordance with the Act Supra

L V SAPTHARISHI, Designated Authority & Addl Secy.